प्रेस इंफार्मेशन सेंटर
www.picmp.com
सामाजिक बदलावों को उजागर करने वाले पत्रकारों का संगठन
-कार्यालय-
ऊपरी भूतल-7,अलकनंदा काम्पलेक्स एमपी नगर,भोपाल.

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जासूस
www.picmp.com बादशाह

अब पढ़िए हर हफ्ते इंटरनेट पर
जासूस बादशाह
प्रेस इंफार्मेशन सेंटर की वेवसाईट लॉग ऑन करें
www.picmp.com

आरएनआई निबंधन संख्या-एमपीएचआईएन-1999 /4107
डाक पंजीयन-म.प्र. /भोपाल /371 / 2009-11
वर्ष-11,अंक-20 (पंद्रह सालों से प्रकाशित) भोपाल,सोमवार 17 मई से 23 मई 2010 तक मूल्य दो रुपया

भू-माफिया बने पत्रकार ,सरकार भी लूट में हिस्सेदार

पत्रकार अरुण कुमार भंडारी के इशारे पर लावण्य गुरुकुल कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी में करोड़ों का घोटाला

भोपाल. देश में चल रही विकास की अंधी दौड़ का असर आम जनजीवन पर साफ तौर पर देखा जा रहा है. लोग रोटी,कपड़ा और मकान की दौड़ में ही सिमट गए हैं और विकास की वास्तविक रफ्तार अब तक जोर नहीं पकड़ सकी है. सेंसेक्स के पैमाने पर बड़े बड़े दावे वास्तविक धरातल पर नकली साबित हो रहे हैं. महानगरों में लोगों को मकान के नाम पर खुलेआम लूटा जा रहा है. राजधानी भोपाल में भू-माफिया ने अपनी करतूतों को अंजाम देने के लिए पत्रकारिता का मुखौटा लगा लिया है. यहां दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार से लेकर छुटभैया पत्रकार तक भू माफिया की अंगुलियों पर नाच रहे हैं. उनका मकसद अब पत्रकारिता नहीं बल्कि सरकारी कानूनों के छेदों में से गिरने वाले चांदी के टुकड़े बटोरना रह गया है.

लावण्य गुरुकुल नाम की ऐसी ही गृह निर्माण समिति की कहानी इस पूरे मामले की पेचीदगियों को उजागर करती है. इस समिति का पंजीयन 1982 में कराया गया था. इसके बाद समिति को लालघाटी के नजदीक पंचवटी कालोनी की जमीन आबंटित की गई. पांच सौ सदस्यों वाली इस संस्था ने 1982 में एयरपोर्ट रोड पर 30.35 एकड़ जमीन खरीदी थी. सदस्यों को जब यह जमीन एयरपोर्ट रोड पर दी गई थी तब इस जमीन की कीमत बहुत कम थी. लेकिन धीरे धीरे इंदौर सड़क मार्ग का विस्तार होता गया इसके चलते यह जमीन करोड़ों की हो गई. तभी से इस भूखंड को हथियाने के लिए कई बिल्डरों ने अपने हाथ पैर मारने शुरु कर दिये. लावण्य गुरुकुल संस्था के लगभग पांच सौ सदस्यों ने इस भूखंड पर अपना मकान बनाने के लिए संस्था की सदस्यता राशि जमा कराई थी. बाद में समिति ने विकास के नाम पर सदस्यों से 35 गुना 60 वर्गफीट आकार वाले भूखंड के लिए 24 हजार रुपए विकास शुल्क के नाम पर जमा कराए. अन्य शुल्क मिलाकर समिति ने सदस्यों से लगभग 48 हजार रुपए जमा करवा लिए. सदस्यों को उम्मीद थी कि उन्हें अब भूखंड अवश्य मिल जाएगा. लेकिन उनमें से अधिकांश सदस्य आज भी अपना घर बनाने का सपना संजोए भूखंड मिलने का इंतजार कर रहे हैं. जब भूखंडों का वितरण चल रहा था तब कल्पना सरकार संस्था की अध्यक्ष थीं. जब कई सदस्यों को भूखंड नहीं मिले तो उन्होंने संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल को इसकी शिकायत की. एक शिकायत कर्ता सदस्य नितिन वर्मा को प्रभारी अधिकारी जे.एस.गुजरावत ने 13.09.2004 को पत्र के माध्यम से बताया कि पूर्व अध्यक्ष कल्पना सरकार के खिलाफ धोखाधड़ी राशि गबन और एक ही भूखंड दो या तीन लोगों को बेचने जैसे मामलों की शिकायत वर्ष 2003 में टीटीनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है.तबसे कल्पना सरकार फरार है.

संस्था अध्यक्ष शरद द्विवेदी ने 6.90 एकड़ जमीन डेवलपर रमाकांत विजयवर्गीय को बेच दी.

इसके बाद संस्था का प्रभार सहकारिता विभाग के निरीक्षक जे.एस.गुजरावत के हाथ आ गया. इस संस्था के घोटालों की कहानियां जब प्रेस तक पहुंची तो मामले को दबाने का ठेका कथित तौर पर यूनाईटेड न्यूज ऑफ इंडिया के पत्रकार अरुण कुमार भंडारी ने ले लिया. उन्होंने अपनी एजेंसी के पत्रकार शरद द्विवेदी को 21 दिसंबर 2004 को अध्यक्ष बनवा दिया. यह सारी कार्रवाई चोरी छुपे ही हो गई. सदस्यों को इसकी सूचना नहीं दी गई. इसके बाद प्रभारी अधिकारी और सहकारी निरीक्षक गुजरावत,शरद द्विवेदी

(शेष भाग पेज 5 पर पढ़िए)

परिवहन माफिया की दबिश में यात्री बस पलटी,कई जख्मी

समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का भाग्योदय करने का दावा करने वाली भाजपा सरकार के शासनकाल में विकास की लहर आम आदमी तक भी नहीं पहुंची है. अंतिम व्यक्ति की हालत क्या है इसका अनुमान सार्वजनिक परिवहन की स्थितियों को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है.सार्वजनिक यात्रा पूरी तरह से परिवहन माफिया की गिरफ्त में पहुंच गई है. इस माफिया पर न तो सरकार का कोई नियंत्रण है और न ही प्रशासन का. फर्जी परमिटों पर बसें चलाई जा रहीं हैं और सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है. इसके बावजूद बसों की धींगामुश्ती के बीच दुर्घटनाएं बढ़ीं हैं और आम आदमी का जीवन असुरक्षित होता जा रहा है.आगे निकलने की होड़ में बसें पलट रहीं हैं और यात्री जख्मी हो रहे हैं.प्रस्तुत है इन्हीं स्थितियों पर एक चौंकाने वाली रपट-

सागर-भोपाल मार्ग पर ओम साईराम ट्रेवल्स नाम से चलाई जा रही यात्री बस सेवा अब हत्यारी बसों और गुंडे मवालियों के प्रबंधन के लिए कुख्यात होती जा रही है. मंगलवार 11 मई को सागर से भोपाल आ रही रहबर ट्रेवल्स की बस कोलू घाट के नजदीक पलट गई. इस दुर्घटना में बस में बैठे यात्रियों को चोटें आईं,लेकिन संयोग से कोई जनहानि नहीं हुई. इस बस में मोटर मालिक भी यात्रा कर रहा था और बस पूरे नियंत्रण में चल रही थी लेकिन बस के का पीछा कर रही ओम साईं राम ट्रेवल्स की बस क्रमांक एमपी 09 एफए 3477 बार बार आगे निकलने की होड़ में लगी थी. इस बस के कंडेक्टर और क्लीनर दुर्घटना ग्रस्त हुई बस के ड्राईवर को धमकियां दे रहे थे. रहबर ट्रेवल्स की बस से पचपन मिनिट बाद चल रही भोपाल की प्रीत ट्रेवल्स की बस के ड्राईवर ने हालांकि बचे हुए यात्रियों को भोपाल पहुंचाया लेकिन तब तक बस को उठाने की व्यवस्था नहीं हो सकी थी और यात्रियों का सामान बस में ही फंसा पड़ा था. प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं थी और यात्रियों को बाहर निकालने का काम आस पास के गांवों के लोग कर रहे थे.

ओम साई राम ट्रेवल्स के प्रबंधक अशोक श्रीवास्तव की हड़प नीति ने इस कंपनी के बेड़े में लगभग 115 बसें शामिल कर दी हैं.सागर बस स्टैंड पर कंपनी का एजेंट मोती बाबा बताता है कि सागर संभाग में हमारी कंपनी की तूती बोलती है.सभी कमाई वाले मार्गों पर हमारी ही बसें चलती हैं. यदि कोई मोटर मालिक अपनी बस चलाने की कोशिश करता है तो हमारे गुर्गे उसका जीना हराम कर देते हैं. इसके बावजूद यदि वह प्रशासनिक या राजनैतिक रूप से ताकतवर होता है तो हमारी कंपनी उसकी बस ही खरीद लेती है.

मोती बाबा ने बताया कि उसकी कंपनी के मालिक अशोक श्रीवास्तव ने भोपाल से चलने वाली प्रीत ट्रेवल्स की बस को दौड़ से बाहर करने के लिए अपनी दो बसें उसके पहले और बाद में चलाना आरंभ कर दीं हैं. एमपी 09 एफए 3477 के ड्राईवर को हिदायत है कि वह प्रीत ट्रेवल्स की बस के आगे आगे चले जबकि एक दूसरी बस एमपी 15 डी 6477 इसके पीछे चलती है. इन दोनों बसों को एक ही परमिट पर चलाया जाता है.

मोती बाबा ने बताया कि कंपनी की ओर से साफ निर्देश हैं कि कोई बस सवारियां न उठा सके. इसके लिए रहबर ट्रेवल्स हो या तिवारी ट्रेवल्स सभी की गाड़ियों को बस स्टैंड पर पांच मिनिट से ज्यादा नहीं ठहरने दिया जाता है. ज्यादा दम खम दिखाने वाले ड्राईवरों कंडक्टरों के मिजाज ठिकाने पर लाने के लिए हमारे लठैत हर वक्त तैनात रहते हैं. बुकिंग काऊंटरों पर बैठने वाले क्लर्कों को भी निर्देश हैं कि केवल ओम साईराम ट्रेवल्स की ही बसों के टिकिट दिए जाएं. इस तरह से पूरा बस स्टैंड हमारे इशारे पर ही चलता है.यदि कोई बस स्टैंड पर दादागिरी कर ले तो शहर की सीमा पर उसकी गाड़ी रोक ली जाती है. ड्राईवर कंडक्टर की इतनी धुनाई हो जाती है कि वे दुबारा कभी सागर के रास्ते पर ही नहीं फटकते.

मोती बाबा कहता है कि ट्रेन से तो गरीब गुरबे ही यात्रा करते हैं. हमारे पास सबसे धनी ग्राहकों की अच्छी आवक है.जिसके सहारे हम दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं.यह पूछने पर कि प्रशासन या पुलिस का खौफ नहीं लगता. उसने बताया कि हमारे आदमी इतनी सख्त निगरानी करते हैं कि अव्वल तो कोई पुलिस थाने में जाने की हिमाकत ही नहीं करता. यदि कर भी ले तो पुलिस ही रिपोर्ट नहीं करती. क्योंकि पुलिस थाने को हफ्ता जाता है. इसी तरह से परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सभी की दस्तूरी बंधी है. परिवहन विभाग को हम एकमुश्त राजस्व भी देते हैं और कमीशन भी इसलिए कोई हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं करता है.

राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होता पूछे जाने पर उसने बताया कि कांग्रेस के नेता सुशील तिवारी से लेकर सभी कांग्रेसी नेता उसकी कंपनी के सहारे ही राजनीति करते हैं. जबकि भाजपा के नेता चंदाखोर हैं इसलिए उनकी इतनी हैसियत ही नहीं कि वे आकर उनके कामकाज में कोई हस्तक्षेप कर सकें. प्रशासन को इस धींगामुश्ती पर अंकुश लगाने की पहल करनी होगी.

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जासूस

बादशाह

भोपाल,सोमवार 17 मई से 23 मई 2010 तक

सार्वजनिक परिवहन का फजीता

देश में सार्वजनिक परिवहन को जिस तरीके से धराशायी किया गया है उसी तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी सार्वजनिक परिवहन की सेवाओं में पलीता लगा दिया गया है. सड़कों के विकास के लिए बजट में तीन हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करने वाले वित्तमंत्री राघवजी भाई ने सार्वजनिक परिवहन को अपनी योजनाओं में पूरी तरह नजरंदाज कर दिया है. जब उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए परिवहन विभाग को ग्रामीण सड़कों पर सस्ती दरों में परमिट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. जब इस योजना पर अमल किया गया तो जो कड़वी हकीकत सामने आई वह दिल दहला देने वाली साबित हो रही है. सड़कों पर परिवहन माफिया ने कब्जा जमा लिया है. यात्रियों को पूरी तरह इस माफिया के हवाले कर दिया गया है और सरकार प्रशासन का इन पर कोई नियंत्रण नहीं बचा है. जनता के धन से बनी सड़कों पर ये माफिया जिस तरह धन उलीच रहे हैं उससे उनकी ताकत बढ़ती जा रही है. आज हालत ये है कि सार्वजनिक परिवहन रोजगार देने का नहीं बल्कि गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का उपक्रम बन गए हैं. ऐसा कभी सार्वजनिक परिवहन के सरकारी क्षेत्र में रहते समय देखने नहीं आया. इस माफिया के बसों के बेड़े पर किसी का नियंत्रण इसलिए नहीं है क्योंकि परमिट देने की व्यवस्था मुक्त बाजार को देखते हुए बनाई गई है. जिसमें दम है वह सड़कों पर राज करेगा वाली तर्ज में चल रहे सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों पर हर पल आतंक का साया चलता है. उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है और भाव ताव करने पर गुंडागर्दी की जाती है. हथियारबंद गुंडों की फौज हर पल तैयार रहती है. प्रतिस्पर्धी मोटर मालिकों को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया जाता है.प्रशासनिक तंत्र में हमेशा से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता रहा है. कभी किसी एक तंत्र का एकाधिकार नहीं होने दिया जाता क्योंकि वर्चस्व हासिल करने के बाद प्रशासन को ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है. सार्वजनिक क्षेत्र के परिवहन में कभी यूनियनों की ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता था आज परिवहन माफिया की मनमानी शर्तों से जनता के खजाने को चोट पहुंचाई जा रही है. एक ही परमिट पर कई गाड़ियां चलाई जा रहीं हैं. उनके चलने के समय बहुत पास पास हैं. परिवहन अमले की मिलीभगत से चलाई जा रही इन बसों से सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंच रही है. बसें तो सड़कों को रौंद रही हैं लेकिन जनता के खजाने में टैक्स तक नहीं पहुंच रहा है. ऐसा नहीं कि सरकार को इन सब बातों की जानकारी नहीं है. लेकिन इस जंगल राज को बढ़ावा भी इसलिए मिल रहा है क्योंकि सत्ताधारी राजनैतिक दलों ने परिवहन के क्षेत्र को चंदा उगाही का तंत्र मान लिया है.राजनेताओं की फौज परिवहन क्षेत्र से होने वाली काली कमाई को लूटने में जुट गई है. यही कारण है कि सार्वजनिक परिवहन के नाम पर खुली लूट को बढ़ावा मिल रहा है. गृहमंत्री उमा शंकर गुप्ता पहले परिवहन मंत्री भी रहे हैं. वे इस व्यवसाय से होने वाली काली कमाई से भी वाकिफ रहे हैं. उन्होंने नया फरमान निकाला है कि पुलिस से परिवहन में जाने वाले अफसरों सिपाहियों को अपने पुलिस अधीक्षक से लिखकर लेना होगा कि उनके जिले में पुलिस बल अधिक है इसलिए उन्हें परिवहन में भेजा जा सकता है. यह परिवहन से होने वाली आय को पुलिस वालों के बीच बंटने से रोकने के लिए उठाया गया कदम बताया जा रहा है. परिवहन आयुक्त पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक हैं. उनसे उम्मीद की जाती है कि वे परिवहन के नाम पर बढ़ रहे इस अपराध के तंत्र पर कोई लगाम लगाएंगे लेकिन सभी बड़े बस अड्डों पर पनप रहे अपराध तंत्र को देखते हुए तो नहीं लगता कि वे अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं. उनके सामने चुनौती है कि वे परिवहन को धन उलीचने का जरिया समझने वाले गुंडा तत्वों या राजनेताओं पर अंकुश कैसे लगाएंगे. उन पर आम नागरिकों को जनसेवा उपलब्ध कराने की बड़ी जवाबदारी है, वे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे कोई ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे सड़कों पर चल रही परिवहन माफिया की धींगामुश्ती पर भी अंकुश लगे और लोगों को सुविधाजनक परिवहन मुहैया कराया जा सके.

जिन्ना से बड़े किसी नेता का इंतजार

-डॉ. वेदप्रताप वैदिक-

पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है, ज्यादातर वक्त वह फौज के शिकंजे में कसा रहा। जाहिर है कि जिन्ना और लिया़कत के सपनों का पाकिस्तान आज भी एक सपना ही है लेकिनउसकी संसद ने १८ वां संशोधन क्या पास किया, बुझे हुए चिरागों में रोशनी पैदा हो गई है।कई लोग मान रहे हैं कि राष्ट्रपति आसिफ ़जरदारी ने ऐतिहासिक साहस और त्याग का परिचय दिया है। उन्होंने अपने पर खुद ही कतर लिये हैं। अब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री या संसद को भंग नहीं कर सकेगा। ़जरदारी अब जिया, इजहाक या मुशर्रफ की तरह अपनी तानाशाही नहीं चला सकेंगे। प्रधानमंत्री युसुफ ऱजा गिलानी अब पाकिस्तान के 'सीइओ' बन गए हैं। क्या यह सच है ?

औपचारिक तौर पर यह सच है लेकिन वास्तविकता क्या है ? सच्चाई यह है कि अब भी सारी शक्तियां आसिफ ़जरदारी के पास ही हैं। १८ वें संशोधन की ९५ धाराओं में से कई ऐसी हैं, जो उन्हें तानाशाह बना देती हैं। एक धारा के मुताबिक पाकिस्तान के राजनीतिक दलों के मुखियाओं को यह अधिकार है कि वे चाहें जिस सांसद को बर्खास्त कर सकते हैं याने पार्टी अध्यक्ष चाहे तो प्रधानमंत्री को पार्टी से निकालकर प्रधानमंत्री पद छोड़ने को मजबूर कर सकता है। ़जरदारी नाम मात्र के राष्ट्रपति जरूर बन गए हैं लेकिन उन्होंने संविधान से ऐसा अधिकार ले लिया है कि उनका प्रधानमंत्री अब नाम मात्र का नेता रह गया है। पिछले दिनोंएक उप-चुनाव में गिलानी ने बहुत जोर लगाया लेकिन वे अपने भाई को टिकिट नहीं दिला सके। वह ़जरदारी के चमचे को ही मिला। यह मामला सिर्फ ़जरदारी और गिलानी के बीच कान हीं रह गया है। सभी पाकिस्तानी पार्टियां खुश हैं क्योंकि सभी का नेतृत्व परिवारवादी है। सभी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही हैं।

मुस्लिम लीग (न) के अध्यक्ष मियां नवाज शरीफ हैं और उनके छोटे भाई शाहबाज पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। मुस्लिम लीग (का.) के अध्यक्ष चौधरी शुजात हुसैन हैं और उनके भाई परवे़ज भी मुख्यमंत्री थे। पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो हैं और उनके पिता आसिफ ़जरदारी सह-अध्यक्ष और राष्ट्रपति हैं। पीपल्स पार्टी की उलझन को ध्यान में रखते हुए १८ वें संशोधन में 'पार्टी अध्यक्ष' शब्द की जगह 'पार्टी मुखिया' शब्द का इस्तेमाल किया गया है ताकि बिलावल की जगह ़जरदारी असली शक्तियों का इस्तेमाल कर सकें। यह प्रावधान बहुत ही आपत्तिजनक है, क्योंकि जो पार्टी अध्यक्ष खुद संसद में नहीं चुना गया है या देश के बाहर रहता है, वह या उसके द्वारा नामजद कोई भी पार्टी

मुखिया चुने हुए सांसद या मंत्री या प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। इस संशोधन ने पार्टी के वार्षिक आंतरिक चुनाव की अनिवार्यता भी खत्म कर दी है। याने अब पाकिस्तान के सांसद अपने पार्टी-अध्यक्षों के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे।

यह संशोधन अब ऐसे प्रधानमंत्री को भी वैधता दे रहा है, जिसे संसद में बहुमत प्राप्त नहीं है। याने पार्टी-अध्यक्ष जिसे चाहे उसे अपनी पार्टी और संसद पर प्रधानमंत्री बनाकर थोप सकता है। यदि अगले चुनाव में पीपल्स पार्टी को बहुमत न मिले तो भी वह राज कर सकती है। इस संशोधन ने वह बंदिश भी उठा ली है, जिसके कारण कोई व्यक्ति दो बार से ज्यादा लगातार प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। नवा़ज शरीफ गद्गद् हैं। दूसरे शब्दों में इस संशोधन ने १९७३ के संविधान के अनेक प्रावधानों की वापसी की है और ज़िया व मुशर्रफ की कारस्तानियों को रद्द किया है लेकिन जन-प्रतिनिधियों को सच्ची सत्ता प्रदान नहीं की है। अभी पाकिस्तान के संविधान का मूल स्वरूप सामंती है।इस संशोधन में यदि ये सामंती प्रावधान नहीं होते तो क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र आ जाता ? इसमें भी शक है। आज भी पाकिस्तान की असली मालिक फौज ही है। सत्ता के बटखरों को एक पलड़े से दूसरे पलड़े पर रख देने से तराजू का चरित्र नहीं बदलता। यदि असली शक्तियां राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री को दे दी जाती तो भी क्या हो जाता ? क्या पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री फौज की सहमति के बिना अपने बालों में कंघी भी कर सकता है ? प्रधानमंत्री मोहम्मद अली, जुल्फिकार अली भुट्टो और मियां नवाज की मिसालें हमारे सामने हैं। पाकिस्तान नामक राष्ट्र का असली एजेंडा अपनी जनता की सेवा, खुशहाली और मजबूती नहीं है बल्कि सिर्फ एकसूत्री है। वह है, भारत से अपनी रक्षा। भारत-भय ही आज तक पाकिस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा निर्णायक-तत्व बना हुआ है। पाकिस्तान की संसद, जनता या नेता इस भारतभय की ग्रंथि के आगे निरर्थक हैं। केवल फौज ही भारत-भय के विरूद्ध एकमात्र गारंटी है। इसीलिए १८ वां संशोधन कितनी ही उठा-पटक कर ले, पाकिस्तानी फौज जिस दिन चाहेगी, पाकिस्तान-सरकार को उठाकर पटक मारेगी। इसीलिए इस संशोधन का भारत-पाक संबंधों पर कोई नाटकीय प्रभाव नहीं होगा।

इसका अर्थ यह नहीं है कि १८ वाँ संशोधन बिल्कुल निरर्थक है। इससे पाकिस्तान की आंतरिक विसंगतियां दूर होंगी। पाकिस्तान के प्रांतों को पहली बार काफी अधिकार मिले हैं। प्रांतों की प्राकृतिक संपदा पर केंद्र और उनका बराबरी का हक होगा। प्रांतों के अपनी नागरिक ही उनके राज्यपाल होंगे। राज्यपालों के अधिकारों में कटौती करके प्रांतीय विधानसभाओं की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। सरकारी नौकरियों में प्रांतीय प्रतिनिधित्व को सुधारा जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मुसल्माना होना अनिवार्य है लेकिन मुख्यमंत्रियों पर से यह अनिवार्यता हटा दी गई है। बलूच और सिंधी राष्ट्रवादी इन कदमों से संतुष्ट नहीं हैं लेकिन इसमें शक नहीं कि अब 'पंजाबी दादागीरी' का पुराना आरोप थोड़ा पतला पड़ेगा। सरहदी सूबे को 'खैबर-पख्तूनख्वाह' नाम देकर पठानों के ़जख्मों पर मरहम जरूर लगाया गया है लेकिन अब इसी सूबे के ह़जारा लोगों ने बगावत की राह पकड़ ली है। सराइकी भाषी भी अब अलग प्रांत की मांग कर रहे हैं। कई नए सिरदर्द ख़डे हो रहे हैं। इस संशोधन में जजों की नियुक्ति अधिक पारदर्शी बनाने का प्रावधान किया है। लेकिन उसे भी अदालत में चुनौती दी जा रही है।

इस संशोधन ने फौजी तख्ता-पलटों को गैरकानूनी करार दिया है और 'मजबूरी के सिद्धांत' को रद्द कर दिया है लेकिन अगर फौज तख्ता पलट कर ही देगी तो नेता क्या कर लेंगे ? उन्हें उसे मजबूरी में मानना ही पड़ेगा। जिन्ना द्वारा ख़डे किए गए इस नकली राष्ट्र को पटरी पर लाने के लिए संविधान के प्रावधान काफी नहीं हैं। जरूरी यह है कि उसका मूल एजेन्डा बदले। यह काम कोई जिन्ना या जिन्ना से भी बड़ा नेता ही कर सकता है। क्या पाकिस्तान के किसी वर्तमान नेता के दिल में कोई ऐसी महत्वाकांक्षा है ?

आखिर कब तक आंखों में धूल झोंकते रहेंगे अश्लील सीडी कांड के हीरो डॉ. शर्मा

भोपाल.व्यभिचार करते सीडी में कैद होने के बाद ब्लैकमेल होते रहे डॉ.अशोक शर्मा को शासन ने एक बार फिर निलंबित कर दिया है.उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरु कर दी गई है. लेकिन इस प्रक्रिया में इतनी खामियां छोड़ी जा रहीं हैं कि जिनका सहारा लेकर यह भ्रष्ट अधिकारी बर्खास्तगी के दंड से बचने की जुगाड़ तलाशने जुट गया है. स्थिति यह है कि प्रशासन उसे दंडित कराने में असहाय महसूस कर रहा है.

स्वास्थ्य विभाग में डॉ.योगीराज शर्मा के बाद डॉ. अशोक शर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद महसूस किया जा रहा था कि गरीबों की दवाई पर डाका डालने वाला गिरोह अब विदा हो गया है. लेकिन डॉ. शर्मा के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उसे देखकर नहीं लगता कि सरकार पर भ्रष्टाचार का धब्बा लगाने वाले इस अधिकारी को उचित दंड देकर बीमारियों से जूझ रहे प्रदेश के आम लोगों के साथ न्याय किया जा सकेगा.

ऐसा मानने के कई आधार साफ नजर आ रहे हैं. विभाग के कर्मचारी नेताओं और स्वास्थ्य विभाग को कई सालों से करीब से देखने वालों का मानना है कि विभाग के भ्रष्ट अफसरों को बचाने वाला दवा माफिया अब भी डॉ. अशोक शर्मा को मरा हाथी सवा लाख का मानकर चल रहा है. भ्रष्टाचार की गंगा बहाने वालों के लिए अब यही वह अधिकारी है जो काली कमाई के सारे राज जानता है. विभाग के मंत्री अनूप मिश्रा से लेकर सचिवालय तक के अफसरों से इसकी सीधी पकड़ है और वह किसी भी हद तक जाकर जनता के खजाने की लूटमार कर सकता है.

शासन के उच्च अधिकारियों के बीच अश्लील सीडी कांड के बाद हुई मंत्रणा में यह पाया गया कि उच्च न्यायालय के जजों से सांठ गांठ करने में भी डॉ. शर्मा ने काफी हाथ पैर मारे हैं. जो बातचीत सीडी में दर्ज है उसमें उच्च न्यायालय के जजों को दी जाने वाली रिश्वत की रकम का भी हवाला दिया गया है. बताते हैं कि इस अधिकारी को ब्लैकमेल करने वाले दरअसल खुद को हाईकोर्ट का दलाल बताते हैं और उनका दावा है कि उनकी ही मदद के कारण इस अधिकारी को हाईकोर्ट से स्थगन मिल सका है.

इस पूरी प्रक्रिया में स्वास्थ्य मंत्री अनूप मिश्रा से लेकर सचिवालय तक के अफसरों की बदनामी हो रही है. क्योंकि इस अधिकारी के खिलाफ जो जांच चालू की गई थी उसका प्रतिवेदन पहले ही तैयार करके सचिवालय भेज दिया गया था.इसके बावजूद एक महीने चार दिनों बाद इस पर सचिवालय ने अपनी सहमति की मुहर लगाई. यह रिपोर्ट हाईकोर्ट में जानबूझकर नहीं भेजी गई. यदि एक साथ छह भ्रष्टाचार के प्रकरणों में जांच की असलियत उजागर हो जाती तो हाईकोर्ट को भी स्थगन देना कठिन हो जाता. 26 मार्च को जैसे ही हाईकोर्ट ने स्थगन दिया उसके बाद 28 अप्रैल को जांच प्रतिवेदन संचालनालय भेजा गया. जबकि इस प्रतिवेदन पर 23 मार्च की तारीख अंकित है.यदि 23 मार्च को तैयार किया यह प्रतिवेदन 26 मार्च को हाईकोर्ट में सरकारी वकील तक पहुंचा दिया जाता तो यह भ्रष्ट अफसर शासन के आदेशों को धता नहीं बता सकता था.

अब जब शासन के आला अफसरों ने इस अधिकारी पर अपनी जांच का शिकंजा कसा है तब उससे जुड़े कई सूत्र जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि जिस सुरेन्द्र उपाध्याय को जांच अधिकारी बनाया जा रहा है वह डिप्टी कलेक्टर स्तर का अधीनस्थ अधिकारी है. उसे डॉ. शर्मा का दुश्मन बताकर जांच अधिकारी इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मिलीभगत से जांच को प्रभावित किया जा सके. इसके अलावा डॉ. शर्मा हाईकोर्ट से जांच अधिकारी की नियुक्ति को ही चुनौती दे सकें.

यदि शासन स्वास्थ्य महकमे की तबियत वास्तव में ही सुधारना चाहता है तो उसे अपने ही स्वास्थ्य आयुक्त मनोहर अगनानी पर भरोसा करना होगा. यह जांच उन्हें सौंप दी जाए तभी संभव है कि गरीब की दवा के नाम पर घोटाला करने वालों का राज फाश हो सके. इसके बाद विभाग के संचालक डॉ.ए.के.मित्तल,संयुक्त संचालक डॉ.राकेश मुंशी,डॉ.के .के .ठस्सू, या डॉ.के .एल.साहू जैसे जानकार अधिकारियों को प्रस्तुत कर्ता अधिकारी बनाया जाना चाहिए.ये अधिकारी प्रकरणों के बारे में भी जानते हैं और उनका तबादला विभाग से बाहर भी नहीं किया जा सकता. जबकि सुरेन्द्र उपाध्याय का तबादला होते ही जांच की प्रक्रिया ढप पड़ जाएगी. यदि प्रस्तुत कर्ता अधिकारी मामले की तह तक नहीं जा सकेगा तो फिर उचित दंड का निर्धारण संभव नहीं है और शासन के आला अफसर अंधेरे में ही रहेंगे.

मौजूदा जांच प्रक्रिया पर ही कई सवाल उठाए जा रहे हैं. जैसे हाईकोर्ट के 26 मार्च के आदेश के बाद स्वत: समझ लिया गया कि डॉ. शर्मा का निलंबन समाप्त हो गया है जबकि इस संबंध में शासन ने कोई आदेश निकाला ही नहीं था. निलंबन समाप्ति का आदेश निकाले बिना शासन ने भी यह कैसे मान लिया कि डॉ.शर्मा निलंबित नहीं हैं और इसके बाद उनकी छुट्टी भी मंजूर कर दी गई.इस दौरान उनका कमरा भी खाली नहीं कराया गया और गाड़ी भी वापस नहीं मांगी गई.छुट्टी पाकर वे हाईकोर्ट में अपनी जमावट करने के लिए दलालों के चक्कर काटने लगे और इसी दौरान उनकी अश्लील सीडी बना ली गई जिससे छूटने के लिए उन्हें कथित तौर पर तीस लाख रुपए देने पड़े.इसके बाद भी जब ब्लैकमेलर उनसे डेढ़ करोड़ की फिरौती मांगने लगे तो उन्हें एसटीएफ की मदद दिलाई गई और ब्लैकमेलरों को पकड़ा गया.

गौरतलब है कि डॉ. शर्मा ने धार में भी ऐसा ही दवा घोटाला किया था.जिसमें जांच अधिकारी कवीन्द्र कियावत और वित्त अधिकारी रहमान ने कथित तौर पर मिलीभगत के बाद उन्हें बेदाग बरी कर दिया था. आज भी यदि उस जांच को किसी सक्षम अधिकारी से कराया जाए तो डॉ.शर्मा के काले कारनामों की कलई उतारी जा सकती है. यदि उस वक्त सही जांच हुई होती तो डॉ. शर्मा तभी बर्खास्त कर दिए गए होते.ऐसे में संचालक के पद पर रहकर उन्होंने सरकारी खजाने को जो करोड़ों रुपयों की चपत लगाई उससे प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती थीं.

जरूरी है कि इस भ्रष्ट अधिकारी को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले नेताओं,अफसरों और दलालों की भी तलाश की जाए ताकि भविष्य में कोई संचालक या अन्य अधिकारी ऐसे गुलगपाड़े न कर सके.

नेताओं अफसरों की तिजोरियां भरने का जरिया बना भारत स्वाभिमान आंदोलन

भोपाल(पीआईसी). देश विदेश में लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव का भारत स्वाभिमान आंदोलन मध्यप्रदेश के नेताओं और अफसरों की कमाई का साधन बन गया है. बाबा रामदेव ने जबसे राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है तबसे भारतीय जनता पार्टी की नींद सबसे ज्यादा उड़ी हुई है. जहां जहां इस पार्टी की सरकारें हैं वहां के नेताओं को कह दिया गया है कि सरकारी तंत्र से आयुर्वेद का इतना प्रचार प्रसार किया जाए ताकि बाबा रामदेव को अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने का मौका ही न मिले.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले से बाबा रामदेव के भक्त रहे हैं.उन्होंने बाबा के योग अभियान को बढ़ावा देने के लिए उन्हें भरपूर सरकारी संसाधन भी मुहैया कराए थे.लेकिन जबसे बाबा ने पूरे सरकारी तंत्र को गरियाना शुरु कर दिया तबसे मुख्यमंत्री जी को नई चुनौती खड़ी होती नजर आने लगी है. इसलिए उन्होंने हाईकमान की सलाह पर गौर करते हुए आयुर्वेद के प्रचार प्रसार पर पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

इस निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनूप मिश्रा की तो लाटरी ही लग गई. सिंचाई विभाग में भजकलदारम का खेल खेल चुके मिश्रा जी को स्वास्थ्य महकमा नीरस सा नजर आ रहा था. क्योंकि यहां उनकी शागिर्दी करते डॉ.अशोक शर्मा को जबलपुर के ठगों ने पकड़ लिया.उन्होंने डॉ.शर्मा को ब्लू फिल्म के हीरो की भूमिका निभाते अपने कैमरे में कैद कर लिया. वैसे भी स्वास्थ्य महकमा डॉ.योगीराज शर्मा और अशोक शर्मा के भ्रष्ट कारनामों के कारण बदनाम हो चुका है. इसलिए कमाई करने वाले अफसरों और नेताओं को अब इस विभाग में दाल गलती नजर नहीं आ रही है.

इस बीच भारतीय चिकित्सा पद्धति संचालनालय में बजट की आवक बढ़ने की खबर पाकर अनूप मिश्रा की छत्रछाया में पल बढ़ रहे कुछ भ्रष्ट अफसरों ने अपना रुख इस विभाग की ओर कर लिया है. इस विभाग के डॉ.बी.सी.जैन को बजट समेटने की जवाबदारी सौंपी गई है. तबसे इन अफसरों ने जिला चिकित्सालयों में ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों को पदस्थ करवाना शुरु कर दिया है जो बजट की हेराफेरी में संचालनालय का पूरा साथ दे सकें. संचालनालय में जमे बैठे इन अफसरों ने विभाग की आयुक्त मधु हांडा को मोम की गुड़िया समझकर अपना जाल फैलाना शुरु कर दिया है.इस गिरोह की रणनीति में आड़े आने वाले कई डॉक्टरों के खिलाफ कर्मचारी संगठनों से शिकायतें करवाई जा रहीं हैं और उनके खिलाफ जांच खोल दी गई हैं.

(पूरी कहानी अगले अंक में पढ़ें.)

देश के दिल से निकली आवाज

सत्ता और शासन तंत्र का जनता से संवाद स्थापित करने में मध्यप्रदेश के पत्रकार तेजी से सफल होते जा रहे हैं. यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यहां पत्रकारों ने बंधी बंधाई लीक को तोड़ा है. सरकार के संसाधनों पर अपनी निर्भरता न रखते हुए पत्रकारों ने आम जनता से सीधे रिश्ते जोड़े हैं. यह बड़ी उपलब्धि है. आज भी सरकारी संसाधनों को लूटकर जनता से विश्वासघात करने वाले पत्रकारों की कमी नहीं हैं. कई संगठन तो केवल इसी के दम पर खुद को जिंदा रखे हुए हैं. वे जनता के नाम पर सरकार से दलाली का कोटा लेते हैं और फिर सरकारी नीतियों की असफलताओं पर चापलूसी भरी जुगाली करते हुए चुप्पी साधे रहते हैं. मध्यप्रदेश के जागरूक पत्रकारों ने पिछले कुछ सालों में ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो देश की नीतियों का मार्गदर्शन करने में सहयोगी साबित हुए हैं. प्रदेश की सरकार भी उन मुद्दों पर गौर करती है और अमल भी करती है. इसके बावजूद सरकार में बैठे कुछ संकीर्ण दिल लोग ऐसे पत्रकारों को श्रेय नहीं देना चाहते. वे पत्रकारों के खून की स्याही से लिखे विचार तो पढ़ते हैं पर उन्हें उसका भुगतान नहीं होने देना चाहते. यह वैचारिक शोषण की पराकाष्ठा है. आज प्रदेश के बड़े अखबार सराकारी प्रचार राशि का अस्सी फीसदी हिस्सा गड़प कर जाते हैं. इसके बावजूद वे जनता के हित की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं. वे उपभोक्ताओं की जेब तराशने वाले कार्पोरेट सेक्टर के सामने पूंछ हिला रहे हैं. लघु और मध्यम समाचार पत्रों के पास संसाधनों का अभाव है इसलिए उनकी आवाज प्रदेश के लोग नहीं सुन पाते हैं. जबकि इन अखबारों में वही पत्रकार काम कर रहे हैं जो बड़े अखबारों में दम तोड़ती अपनी वैचारिक भूख को मिटाना चाहते हैं. सरकार जानती है कि यदि लघु और मध्यम समाचार पत्रों को मजबूत बना दिया जाएगा तो फिर सरकारी तंत्र की पोल जगह जगह खुलेगी. जो सरकारी तंत्र जनता के संसाधनों का अस्सी फीसदी से अधिक हिस्सा केवल अनुत्पादक स्थापना बजट के रूप में ही खर्च कर देता हो उससे आखिर विकास की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है. इसके लिए कोई एक सरकार दोषी नहीं है. बल्कि पूरी प्रशासनिक राजनैतिक व्यवस्था दोषी है. सरकार को मालूम है कि वह कर्मचारियों पर जो व्यय कर रही है उसका जनता के लिए कोई उपयोग नहीं है. आदर्श व्यवस्था तो यह है कि जनता के संसाधनों का अधिकतम 12 फीसदी हिस्सा स्थापना पर खर्च किया जाए. शेष राशि विकास कार्यों पर खर्च की जाए. लेकिन आज बजट से भी ज्यादा राशि सरकार चलाने पर खर्च हो रही है. विकास कार्यों के लिए कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है.यही कारण है कि जनता में असंतोष गहराता जा रहा है. राज्य सरकारें केन्द्र को दोषी बता रहीं हैं और केन्द्र अपनी असफलताओं का ठीकरा राज्य सरकारों पर थोप रहा है.इस नूराकुश्ती के बीच नक्सलवाद का लाल डोरा अपना जाल फैलाता जा रहा है. इस तंत्र को जनता का सहयोग मिल रहा है. वह भी केवल इसलिए कि लोग अनाचार की इस व्यवस्था को अब अधिक झेलने के लिए तैयार नहीं हैं. सरकार को इस परिस्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे. उसे कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना छोड़कर अब बेहतर प्रशासनिक तंत्र वाली लाभदायी व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने होंगे. इसके मार्ग में रुकावट खड़ी करने वाले भ्रष्ट तंत्र को नेस्तनाबूत करना होगा. भ्रष्ट अधिकारियों को कड़े फैसलों की सर्जरी से उखाड़ फेंकना होगा. सरकार को रोजगार देने वाली व्यवस्था मानने की सोच बदलना होगी. यह तभी संभव है कि जब लोगों को आत्मनिर्भर संसाधन तलाशने का मौका दिया जाए.सरकार को चाहिए कि वह बेहतर संवाद तंत्र स्थापित करने वाले अखबारों को बढ़ावा दे और केवल रोजगार के लिए पत्रकारिता करने वाले लोगों को वैकल्पिक आय के साधन मुहैया कराए. संवाद तंत्र को कुशल बनाकर सरकार जनता से बेहतर संवाद स्थापित कर सकती है. यह कदम राज्य के हित में बहुत सहयोगी साबित होंगे. आईसना ऐसे पत्रकारों का संगठन है जो केवल रोजगार के लिए पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को बढ़ावा नहीं देता. इस संगठन का लक्ष्य प्रदेश में और देश में कारगर संवाद उपलब्ध कराना है.इसलिए जरूरी है कि सरकार आईसना के वैचारिक मंथन से निकले अमृत का पान करे और चैतन्य होकर आदर्श लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाएं.**अवधेश भार्गव**

छोटे अखबारों को भी जिंदा रखें आयुक्त महोदय

जनसंपर्क विभाग के नए आयुक्त राकेश श्रीवास्तव की इंदौर में कलेक्टर के रूप में दी गई सेवाएं उल्लेखनीय रहीं हैं. वे इंदौर में सौम्य प्रशासनिक सुधारों के लिए याद किए जाते हैं. इंदौर के लोगों को बरसों बाद ऐसा जिलाधीश मिला था जिसने बगैर राजनीतिक

(राकेश श्रीवास्तवः सौजन्यता ने जगाई आस)

भेदभाव किए लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था. शासन ने उनकी उसी शैली को देखते हुए उन्हें जनसंपर्क महकमे की जवाबादारी सौंपी. जनसंपर्क महकमे में लंबे समय से नीतिगत प्रशासनिक सुधारों की जरूरत महसूस की जा रही है. पुराने आयुक्त ने सरकार की सुविधा को देखते हुए जो व्यवस्था विकसित की थी उसके कारण कई छोटे अखबारों के पत्रकार उपेक्षित महसूस कर रहे थे. जनसंपर्क विभाग की प्रशासनिक जमावट में भी कई असंतुलन थे जिसके चलते विज्ञापन शाखा की कार्यशैली विवादास्पद बन गई थी. अब जबकि व्यवस्था बदली है तब उम्मीद की जाती है कि नए कमिश्नर महोदय विज्ञापन जैसी संवेदनशील शाखा में ऐसे लोगों की तैनाती करेंगे जो पत्रकारों के प्रति द्वेष भाव तो न रखें.

ऐसे याद की जाएंगी सेवाएं

डॉ.अशोक शर्मा के कारनामों से मध्यप्रदेश का स्वास्थ्य महकमा खुद को बहुत असमंजस में पा रहा है. शासन ने इस बिगड़ैल अधिकारी को बचाने के लिए तमाम प्रशासनिक परंपराओं को धता बता दिया है.इस अधिकारी पर लोकायुक्त संगठन में भ्रष्टाचार के छह प्रकरण लंबित हैं.यदि इन छह प्रकरणों की जानकारी हाईकोर्ट के सामने रख दी जाती तो अदालत भ्रष्टाचार के हुनर में सिद्धहस्त इस अधिकारी की रवानगी तत्काल डाल देती. इसलिए शासन के विद्वान अफसरों ने इन सभी प्रकरणों के बारे में अदालत को अंधेरे में रखा . जिसके चलते इस भ्रष्ट अफसर को अदालत से स्थगन मिल गया. विभाग के प्रशासनिक अफसर श्री उपाध्याय ने इन प्रकरणों पर चार्जशीट तैयार करके 24 मार्च को शासन के सामने भेजा था. लेकिन यह फाईल पूरे एक महीने चार दिन तक शासन के पास लंबित रही. जब 26 मार्च को विभाग ने हाईकोर्ट के सामने कोई जवाब नहीं प्रस्तुत किया तो सरकारी वकील के पास तर्क करने के लिए कोई मसाला ही नहीं था. नतीजतन डॉ.को कोर्ट से स्थगन मिल गया. शासन ने आरोप पत्र वाली फाईल 28 मार्च को विभाग के पास लौटाई. लेकिन अब तक इस फाईल का कोई उपयोग नहीं बचा था. तब तक डॉ. अशोक शर्मा को विभाग में अपनी उपस्थिति बनाए रख सकने के लिए एक मौका तो मिल ही गया है. विभाग के सूत्र बताते हैं कि अब राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उपाध्याय पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह किसी तरह इस फाईल को अदालत तक न पहुंचने दें.इसके लिए डॉ. अशोक शर्मा की सेवाएं ली जा सकती हैं

अंधेरा कायम रहे

सरकार ने इंदौर कलेक्टर रहे राकेश श्रीवास्तव को जनसंपर्क आयुक्त बनाकर भेजा है. उन्होंने सरकार के हुक्म को सर आंखों पर रखकर अपनी नई कुर्सी संभाल भी ली. लेकिन वे जैसे ही नई कुर्सी पर बैठे वैसे ही कार्यालय की बत्ती गुल हो गई. थोड़ी देर बाद प्रदेश से सीधा संवाद करने वाली इस कुर्सी पर बैठकर साहब ने अंधेरे में ही अपने कामकाज का जायजा लिया. जैसे ही वे उठकर बाहर जाने लगे तो लाईट आ गई. अब इस घटना में कोई षड़यंत्र था या संयोग इसकी खोजबीन तो नहीं हो पाई.लेकिन देखने वालों ने चुटकी ली कि पुराने कमिश्नर साहब कह गए थे कि यहां के सारे काम अंधेरे में ही होते हैं. सो इस परंपरा को कायम रखा जाएगा.

पत्रकारों से नहीं बदनीयती से भयभीत रहें

जनसंपर्क विभाग के नए कमिश्नर ने कुर्सी संभाली नहीं कि पत्रकारों ने उन्हें अपने हुनर का दर्शन करा दिया. भोपाल से प्रकाशित एक पत्रिका ने इंदौर के आरएनटी मार्ग स्थित नमन सेन्ट्रल मॉल के निर्माण में आपत्तियों का निराकरण किए बगैर प्रशासन की एनओसी जारी करने वाले मामले में दर्ज लोकायुक्त प्रकरण का हवाला छाप दिया. इस प्रकरण में तत्कालीन कलेक्टर और वर्तमान जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव समेत छह अफसरों पर जांच प्रकरण कायम किया गया है.साहब को नई कुर्सी संभालते समय भय लग रहा है कि कहीं पत्रकार इसे कैलाश विजयवर्गीय जैसा मामला न बना दें. पत्रकारों में साहब के चेहरे पर उड़ती हवाईयां देखकर चर्चाएं होने लगीं कि पिछले तो खूब टिके पर इनका मन छह महीने में ही भर जाएगा. साहब को पत्रकारों की नेक सलाह यह है कि वे कायस्थ लॉबी के फेर में न पड़कर ईमानदारी से काम करें. पत्रकार न तो उनके दुश्मन हैं और न ही प्रदेश के दुश्मन. निवेदन केवल इतना है कि बदनीयती को अपने कमरे में भी न घुसने दें. आप भलमनसाहत रखेंगे तो यह कार्यकाल आपके लिए यादगार बन जाएगा.

मुंबई में 1000 टैक्सियां किसकी

हरफन मौला मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगाने वाले तरह तरह के शिगूफे ढूंढने में लगे हैं. उन्हें जमीन घोटाले में घेरने के प्रयास जब कमजोर होते नजर आने लगे तो पत्रकारों ने इंदौर में चल रहीं 100 रेडियो टैक्सियों के मालिक के बारे में चर्चाएं शुरु कर दीं. यह टैक्सियां कथित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने फाईनेंस कराकर खरीदीं हैं. जब इस मसले पर कुछ पत्रकारों ने भोले भंडारी से सवाल किया तो उन्होंने उलटा सवाल किया कि जरा ये भी मालूम कर लें कि मुंबई में हजार टैक्सियां किस राजनेता की चल रहीं हैं.मैं तो बहुत छोटा सा सेवक हूं. गौरतलब है कि कथित तौर पर ध्रुवनारायण सिंह की रेडियो टैक्सियां भोपाल में भी चल रहीं हैं और इन टैक्सियों को 12 रुपए प्रति किलोमीटर का किराया तय करने के लिए सरकार ने बाकायदा अधिसूचना जारी की है. इसके बाद से महानगरों में टैक्सियों पर लोन कराने की होड़ लग गई है. क्योंकि एक साथ सौ से ज्यादा टैक्सियां हो जाने पर नेताओं को कमाई भी होने लगती है और उनके समर्थकों

की भीड़ भी हरदम तैयार रहती है.

मंत्रीजी को अबकी किसने किया ब्लैकमेल

सरकार के एक बुजुर्गवार मंत्रीजी अपनी रंगीन तबियत के कारण एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं. हालांकि अब ऐसे मामले ट्रेकिल करने का अब उन्हें लंबा अनुभव हो गया है. बताते हैं कि उनके किसी विश्वस्त ने इस बार बिल्कुल साफ वीडियो फिल्म उतार ली है. लेकिन उस फिल्म को प्रस्तुत करने के लिए उसने एक पत्रकार का सहारा लिया. जाहिर है कि मंत्रीजी ने डैमेज कंट्रोल की कहानी दुहराई और फिल्म उतारने वाले को खासी रकम भी भेंट की. इस प्रेमालाप में कथित तौर पर नई आत्मा ईजाद करने वाली मंत्रीजी की सहेली का भी घर बसा दिया गया है. वह भी पर्याप्त भेंटपूजा करके.

खूब फले गरीबों के मकान

गरीबों के लिए बनाए जाने वाले मकान सरकार के एक मंत्रीजी के लिए खूब फल रहे हैं. इसके लिए उनके निर्माण के पुराने नियमों में थोड़ा फेरबदल करना पड़ा है. पर मंत्रीजी को भय है कि कहीं उनकी लक्ष्मी पर किसी शोहदे की नजर न पड़ जाए सो उन्होंने लक्ष्मी की देखभाल की जवाबदारी पार्टी के बुजुर्ग नेता को सौंप दी है.

क्यों खुला रहता है मुंह गौर का

भाजपा के कार्यकर्ता अपने नेताओं के बताए मार्ग पर चलने के लिए बहुत लालायित रहते हैं. इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता अपने दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की भाषण शैली की नकल करते देखे जाते हैं. उनकी भाषण शैली बहुत प्रभावी थी इसलिए कार्यकर्ताओं के अंदाज को भी लोगों ने भरपूर प्यार दिया. मगर कुछ नेताओं की भाव भंगिमा कार्यकर्ताओं के लिए सिरदर्द बन गई है.जैसे भोपाल के भाजपा नेता बाबूलाल गौर का खुला मुंह बहुत कुछ कहता नजर आता है. विश्वास सारंग के पोस्टरों पर लगे चित्रों में भी ऐसा ही कुछ देखने मिलता है.गौर बुजुर्ग हैं और सारंग युवा.इसलिए लगता है कि युवा पीढ़ी ने अपने बुजुर्ग नेता की नकल करना शुरु कर दी है. भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच नेताओं के मुंह खुला होने के कुछ अलग ही स्पष्टीकरण हैं. उनका कहना है कि जिन नेताओं की डिमांड ज्यादा है उनके मुंह खुले रहते हैं.

और डेवलपर रमाकांत विजयवर्गीय ने मिलकर भूखंडों की कालाबाजारी शुरू कर दी. इस कारोबार में इस तिकड़ी ने भरपूर मुनाफा कमाया.हर भूखंड

ए.के.भंडारी-जालसाजों का मास्टरमाइंड

बाजार मूल्य से भी ज्यादा रकम लेकर बेचे गए. संस्था के सदस्य लगातार गुहार लगाते रहे कि उन्हें भूखंड पाने का हक है लेकिन दस्तावेज गुम जाने का बहाना बनाकर उन्हें टरका दिया जाता रहा.

दो सदस्यों ने जब उपभोक्ता फोरम में शिकायत की तो फोरम ने उन्हें भूखंड दिए जाने का आदेश पारित कर दिया. इसके बाद संस्था के अध्यक्ष शरद दिवेदी ने डेवलपर रमाकांत विजयवर्गीय के माध्यम से दोनों सदस्यों को पत्र भिजवाया कि वे दो हजार रुपए वर्गफीट की दर से रकम जमा कराएं तभी उन्हें भूखंड मिल सकता है. वरना जहां शिकायत करना चाहें कर लें. क्योंकि यूनाईटेड न्यूज आफ इंडिया अब इस सौदे में शामिल है और यह अतिरिक्त रकम समाचार एजेंसी को भिजवाई जानी है. इस कहानी को बल देने के लिए उन्हें बताया गया कि समिति में यूएनआई के अठारह कर्मचारियों को कालोनी में भूखंड दिलाए गए हैं. ये सभी कर्मचारी पत्रकार नहीं थे लेकिन इन्हें भंडारी ने समिति का सदस्य बनवा दिया. इनमें पत्रकारों के अलावा इंजीनियर,बाबू और चपरासी सभी शामिल थे. इन कर्मचारियों को चूंकि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर मोटा वेतन मिलता रहा है इसलिए इनसे जैसा कहा जाता रहा वे करते रहे.

पूर्व अध्यक्ष शरद दिवेदी ने समिति के भूखंडों के पंजीयन में चमत्कार कर दिखाया. उन्होंने एक ही दिन में दिनांक 2.3.2005 को 118 रजिस्ट्रियां अपने हस्ताक्षरों से करवाईं. वैसे तो उनके हस्ताक्षर कुल 177

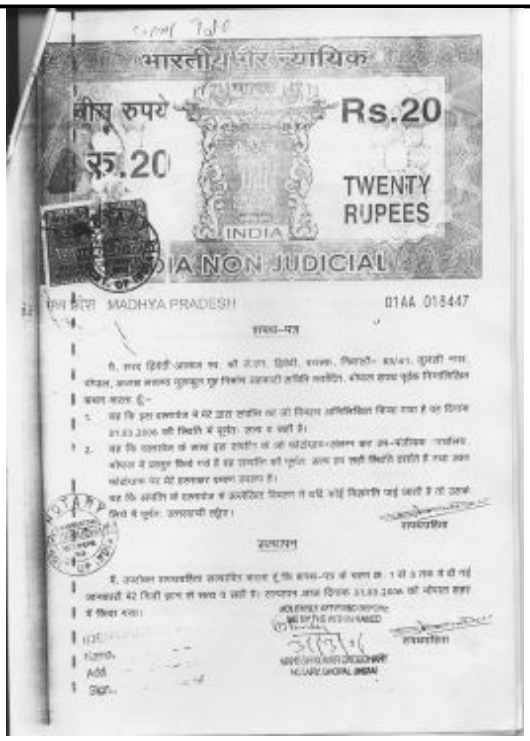

(बेची गई 7 एकड़ जमीन के लिए अध्यक्ष शरद दिवेदी का शपथ पत्र)

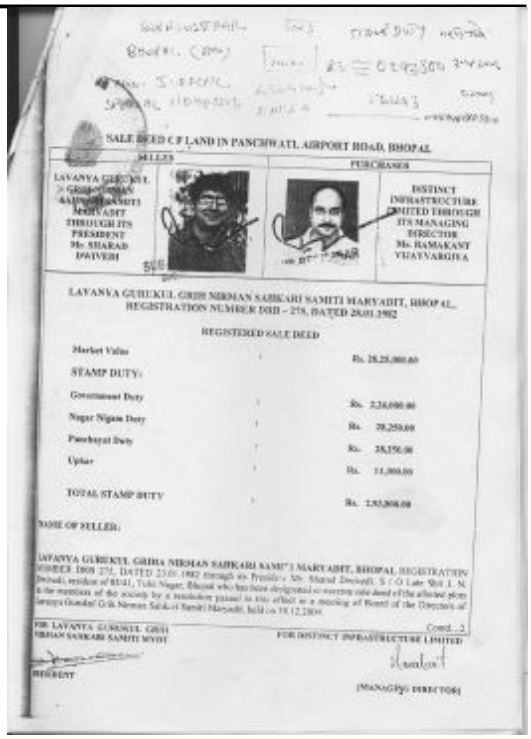

(शरद दिवेदी और रमाकांत विजयवर्गीय के बीच हुआ पंजीकृत विक्रय पत्र)

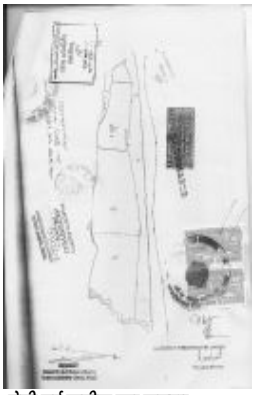

बेची गई जमीन का नक्शा

भूखंडों के पंजीयन दस्तावेजों पर मौजूद हैं,लेकिन उनमें से सिर्फ 46 लोगों के नाम ही सदस्यता सूची में मिले हैं.बाकी 131 भूखंड उन्होंने बाजार मूल्य पर किसे और कब बेचे यह जांच का विषय है.क्योंकि ये सभी खरीददार संस्था के सदस्य ही नहीं हैं. इसके साथ ही शरद दिवेदी ने संस्था की 6.90 एकड़ बेशकीमती जमीन जिला इंफ्रास्ट्रक्चर लि.के मैनेजिंग डायरेक्टर रमाकांत विजयवर्गीय को एकमुश्त बेच दी. इस कंपनी से जमीन के एवज में 28 लाख 25 हजार प्राप्त किए गए. वार्ड नं.4 ग्राम हलालपुरा की इस जमीन की रजिस्ट्री 31.3.2006 को कराई गई. यह दस्तावेज पुस्तक जिल्द क्रमांक 5647 क / अ-1 / 23936 के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है. घोटाले की इस कहानी की असली तस्वीर और भी चौंकाने वाली है. एकमुश्त बेची गई जमीन से प्राप्त रकम आज तक संस्था के खाते में नहीं आई है. श्री दिवेदी ने जो 177 भूखंड बेचे उनका पैसा भी संस्था के खाते में नहीं आया. जाहिर है कि संस्था के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अमानत में खयानत की है.

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक जे.एल.गुजरावत ने भी कुछ इसी तरह का काम किया है. घोटालों की फेरहिस्त बढ़ाते हुए उन्होंने भी 148 भूखंडों की रजिस्ट्रियां कराई हैं. 11.10.2004 को उन्होंने भी एक ही दिन में 107 रजिस्ट्रियां करवाकर रिकार्ड बनाया. संस्था के सदस्य नितिन वर्मा को 13.09.2004 को पत्र क्रमांक प्रा.अ. / 04 / 7 के माध्यम से श्री गुजरावत ने जबाब दिया कि शिकायत कर्ता को भूखंड दिलाना उनकी कार्य परिधि से बाहर है. यदि इस दस्तावेज में कहा गया उनका कथन सही माना जाए तो फिर प्रभारी अधिकारी के रूप में उन्होंने इतनी सारी रजिस्ट्रियां आखिर कैसे करवा लीं.

सहकारिता विभाग के पास मौजूद रिकार्ड के अनुसार संस्था के विकास की जवाबदारी रमाकांत विजयवर्गीय की फर्म की थी. इसके एवज में नगर निगम में बंधक रखे गए 75 भूखंडों को गुजरावत ने झांसा और रिश्वत देकर पहले अपने नाम करवा लिया और बाद में वे भूखंड डेवलपर को सौंप दिये.इस सौदे को दस्तावेज / पुस्तक /जिल्द क्रमांक 3945 क / अ-1 / 20299 वार्ड क्रमांक-1 हलालपुर पर अंकित कराया गया है.

इस घोटाले की कहानी का पर्दाफाश न हो सके इसके लिए इन सभी जालसाजों ने लावण्य गुरुकुल संस्था का नाम बदलकर पंचवटी कालोनी कर दिया. जब सदस्य अपने भूखंड का दावा करने संस्था के कार्यालय पहुंचते थे तो उनसे कहा जाता था कि कल्पना सरकार भाग गईं हैं और यह जमीन पंचवटी नगर की है. आपको जहां शिकायत करनी है कर लें.

पंचवटी संस्था के डेवलपर रमाकांत विजयवर्गीय ने 2007 में कालोनी खाली पड़ी जमीन पर फेस 3 बनाने का दावा किया लेकिन जब प्लॉट देने की बारी आई तो बताया गया कि यह जमीन रासलाखेड़ी में खरीदी जा रही है. जब लोगों ने विजयवर्गीय की घेराबंदी की तो उसने उन्हें कुछ राशि के चैक थमा दिए जो बाद में बैंक में बाऊंस हो गए.इसकी शिकायत कुछ लोगों ने कोहेफिजा पुलिस थाने में जाकर की.

लावण्य गुरुकुल गृह निर्माण समितियों के सदस्यों का कहना है है कि समिति के कारनामों का खुलासा होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. उन्होंने सितंबर 2009 में जन सुनवाई में अपनी शिकायत प्रशासन से की है. सहकारिता विभाग ने भी गड़बड़ी किया जाना स्वीकार किया है लेकिन सदस्यों को भूखंड दिलाने के मामले में उसकी भी बोलती बंद हो जाती है. ये सभी सदस्य पिछले सात सालों से जमीन का टुकड़ा पाने के लिए आवाज उठा रहे हैं. इस हो हल्ले का नतीजा यह निकला कि विभाग ने आर के खत्री को जांच अधिकारी के रूप में ओआईसी बना दिया गया.

शिकायत करने वाले बताते हैं कि सहकारिता विभाग के उपायुक्त एच.एस.वाघेला कहते हैं कि हमने संस्था भंग करके जांच के लिए ओआईसी तैनात कर दिया है. उनका कहना है कि संस्था भंग करने से पहले शरद दिवेदी उसके अध्यक्ष थे. उन्हें पद से हटाकर अब यह जांच की जा रही है. वाघेला यह भी कहते हैं कि गुजरावत के रिटायर हो जाने के कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है. जबकि किसी कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि यदि कोई अपराधी छूट जाए तो दुबारा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी. जबकि संस्था के पदाधिकारियों के करोड़ों के घोटाले में गुजरावत का भी सहयोग था.

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने विधानसभा में यह घोषणा की थी कि गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वे कितने ही ताकतवर क्यों न हों. इस मामले में भी धोखे का शिकार हुए संस्था के सदस्य उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो दिन जरूर आएगा जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें न्याय दिलाएंगे और बरसों पुराना उनका अपने घर का सपना पूरा करेंगे.

रामस्वरूप गढ़वाल: लाख के जेवरों में भरा सौ टंच से सोने सा भरोसा

रामस्वरूप से भी एमओयू करें, कैलाश जी

भोपाल(पीआईसीएमपीडॉटकॉम).उद्योग और ग्रामोद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों एक ऐसे प्रस्ताव के कारण भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं जिसे शासन ने मंजूरी न देने के बाद खारिज कर दिया है. इंदौर में कथित जमीन घोटाले के इस प्रकरण में हस्तक्षेप के कारण कैलाश इन दिनों बड़े झमेले में पड़ गए हैं. करोड़ों के इस अनुबंध को हरी झंडी देने के साथ साथ यदि कैलाश ने गांवों में छोटे उद्योग चलाने वालों से अनुबंध किया होता और उनके माल की मार्केटिंग को बढ़ावा दिया होता तो आज शायद उनकी राजनीतिक साख सान पर नहीं चढ़ गई होती.

मध्यप्रदेश शासन के ग्रामोद्योग विभाग को तो शायद मालूम भी नहीं होगा कि राजधानी से सौ किलोमीटर के दायरे में रहने वाला रामस्वरूप अपने बनाए कलात्मक माल की मार्केटिंग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है. पहले तो उसने इस कला को सीखने में अपनी जिंदगी के आधे से ज्यादा बसंत गुजार दिए अब वह माल की मार्केटिंग से जूझ रहा है.उसे लगता है कि न जाने कब उसके भाग्य का सूर्योदय होगा और उसकी कला गरीबों का पेट पालने में सहयोगी साबित होगी.

सौंदर्य के कारोबारियों ने तरह तरह के आभूषण ईजाद किए हैं.कुछ बहुत मंहगे हैं तो कुछ फूलों के गहनों की तरह मन को छू लेते हैं. रामस्वरूप के बनाए गहने भी इतने सुंदर हैं कि सोने के आभूषण उनके सामने फीके नजर आते हैं. मजबूत इतने कि गांवों की गोरियां उन्हें पहिनकर खेती किसानी के काम भी बेफिकी से करती हैं. अपनी इस आभूषण कला को निखारने के लिए रामस्वरूप ने देश दुनिया की खाक छानी है और बरसों तक अपनी इस प्रयोगधर्मिता के चलते लोगों के लांछन सहे हैं. इस सबके बाद उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी और लोगों से किए वादे निभाने के लिए कई जोखिम लिए. आज भी वह अपने आभूषणों की विश्वसनीयता साबित करने के लिए उन्हें सस्ते दामों पर बेच देता है. उसका प्रस्ताव इतना खरा होता है कि लोग उसे ढूंढ़ते हैं और बुलाकर ढेरों आभूषण बनाने का प्रस्ताव देते हैं. लोगों की नजर में यदि रामस्वरूप अपनी दम पर विश्वसनीयता का पैमाना बन गया है तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि भीड़ में भरोसे की अलख जगाते ऐसे शिल्पी को ढूंढ़कर उसे समाज में स्थापित करे.

होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के बनापुरा गांव में रेलवे फाटक के नजदीक रहने वाला रामस्वरूप अपनी पत्नी और बेटे के साथ आभूषण बनाता है. उन्हें सजाता संवारता है और फिर होशंगाबाद आकर व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेच देता है. क्योंकि उसके माल का विपणन करने लायक ढांचा उसके पास नहीं हैं. उसने यह कला बरसों की मेहनत के बाद सीखी है. इस कला से रोजगार पाने का मार्गदर्शन उसने देहाती पुस्तक भंडार दिल्ली से प्रकाशित (एक हजार छह उद्योगों की जानकारी)नामक किताब से पाई थी. इसके बाद जब वह लाख के जेवर बनाने बैठा तो सारा माल बिगड़ गया पर जेवर न बन सके. अपनी धुन का पक्का रामस्वरूप इसे सीखने के लिए जयपुर गया और फिर वहां से नग और जेवर बनाने का कच्चा माल खरीदकर लाया. इसके बाद उसने कई प्रयोग किए और ऐसे मजबूत लाख का निर्माण किया जो तीन चार फीट ऊंचाई से गिराने के बाद भी टूटता नहीं था. आज उसके लाख की मजबूती ही उसकी विश्वसनीयता का आधार बन गई है. जैसा लाख रामस्वरूप बनाता है वैसा माल तो इन जेवरों का पारंपरिक धंधा करने वाले लखेरे भी नहीं बनाते. जब कोई ग्राहक उसके जेवरों को खटाऊ बताता है तो रामस्वरूप की आंखें चमक उठती हैं.

बेटे को पढ़ालिखाकर इंजीनियर बनाने के सपने आंखों में संजोए इस खांटी ग्रामीण शिल्पकार की निगाहें भविष्य के सपने देख रहीं हैं.उसका कहना है कि मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं सका लेकिन चाहता हूं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने और समाज के रचना धर्मी लोगों को सहारा देकर मजबूत हिंदुस्तान की नींव रखे.

वह सवाल पूछता है कि यदि वह अपने हुनर से शिल्पकला का विकास कर सकता है तो फिर बच्चों को इंजीनियर बनाने की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है. वह कहता है कि सरकार यदि प्रयास करे तो गांवों की धरती पर ऐसे कई जवाहरात मिल जाएंगे जो देश की तमाम तकनीकी समस्याओं को चुटकियों में दूर कर देंगे.

ग्रामोद्योग के अलावा कई महत्वपूर्ण विभागों की जवाबदारी संभालने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर इंदौर में नंदानगर सहकारी साख संस्था की ओर से खरीदी गई सुगनीदेवी कॉलेज वाली जमीन के सौदे में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि धनलक्ष्मी केमिकल इंडस्ट्रीज से खरीदी गई इस जमीन के सौदे पर विजयवर्गीय ने महापौर रहते हुए अपनी सहमति दी थी.

जबकि यह प्रस्ताव शासन ने हालिया बवेले के बाद खारिज कर दिया है. यदि कैलाश विजयवर्गीय उद्योगपतियों से किए जाने वाले करारों के साथ साथ गांव के हुनरमंद शिल्पकारों से करार करते तो शायद उन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ते. जाहिर है कि एक बड़ी गलती को सुधारने का इससे अच्छा मौका शायद कैलाश विजयवर्गीय को अब शायद न मिल सके. उन्हें अपनी भूल सुधार के लिए अब रामस्वरूप गढ़वाल के मोबाईल नंबर -8109251006 (आठ एक शून्य नौ दो पांच एक शून्य शून्य छह)पर संपर्क करना चाहिए.

ग्रामीण विकास की आवाज को बुलंद करके वे ऐसे कई झमेलों से मुक्ति पा सकते हैं. उन्हें याद होगा कि इंदौर के अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष नितिन गड़करी ने भी तो ऐसे ही शिल्पियों को बढ़ावा देने की बात कही थी.आप बेशक शादियां कराएं पर धंधों को भी तो बढ़ाएं.

किसके इशारे पर चल रही है सिंधिया राजघराने को बोंसाई बनाने की साजिश

भोपाल(पीआईसीएमपीडॉटकॉम). मध्यप्रदेश की राजनीति में पहली बार सत्ता के ढेरों टापुओं का उदय होता देखा जा रहा है. इन टापुओं पर अपना झंडा फहराने की चाहत ने राजनीति के लड़ाकों के बीच जबर्दस्त घमासान की स्थितियां भी निर्मित कर दीं हैं. लोगों को ऐसे ही एक क्षत्रप के रूप में जूनियर सिंधिया का भी उदय होता नजर आ रहा है. इसीलिए जूनियर सिंधिया को अभी से बोंसाई बनाने के प्रयास शुरू हो गए हैं. पिछले दिनों राजधानी में सिंधिया राजघराने की राजनीति पर जो दंड पेली गई उसने राजनीति के कई पंडितों के कान खड़े कर दिए हैं.प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार परेशान है क्योंकि उसकी शासन की शैली पर लोगों के कानों में वाह वाही सुनाई नहीं दे रही है. शिव के शासन का आकलन आने वाले कल में ही किया जा सकेगा. लेकिन शिव की विनम्र शासन शैली के बीच कई क्षत्रपों को अपना कल सुनहरा नजर आ रहा है. कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के कई नेता इन हालात का फायदा उठाने को तैयार खड़े हैं.

पिछले दिनों केन्द्रीय राज्य मंत्री और कैलाशवासी माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी पहुंचे. सिंधिया खेमे ने उनके इस दौरे को महिमा मंडित करने के बहुत सारे उपाय किए,लेकिन वे सभी उपाय कोई अच्छा संदेश न दे सके. बल्कि बिखड़ी अंदाज में हुआ सिंधिया का स्वागत राजनीति के जानकारों की नाराजगी का कारण बन गया. सिंधिया केम्प ने जिन लोगों को अपनी पैरवी के लिए चुना वे निहायत उथले साबित हुए.

होटल पलाश में आयोजित कार्यक्रम में दैनिक भास्कर के मालिक रमेश अग्रवाल ने सिंधिया के मंच पर आकर कांग्रेस की राजनीति में अपनी उपस्थिति दिखाने की कोशिश की. कहा जाता है कि भास्कर पत्रसमूह आजकल दस जनपथ के निशाने पर आ गया है. शायद यही कारण है कि अग्रवाल ने अपने बेटों के बराबर जूनियर सिंधिया के मंच से केन्द्र की नीतियों का समर्थन किया. नक्सलवाद को उन्होंने केन्द्र की आर्थिक नीतियों की असफलता न बताकर कहा कि नक्सलवादी तो पढ़े लिखे नहीं हैं. यदि उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर दी जाए तो नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा. जूनियर सिंधिया ऐसी सतही टिप्पणियों के सामने सिर हिलाते नजर आए. जबकि मध्यभारत में सिंधिया राजघराने ने सबसे ज्यादा विद्रोहियों का सामना किया है. उन्हें बागी का तमगा देकर सामाजिक न्याय को लागू करने के प्रयास भी मध्यभारत में ही हुए. आज उसी राजघराने का शावक यदि नक्सलवादियों को कम पढ़ा लिखा बताते समय चुप रहता है तो इससे उसकी राजनैतिक प्रतिभा धूल धूसरित होती नजर आती है.

इस कार्यक्रम के बाद सेन्ट्रल प्रेस क्लब नाम की संस्था ने जो पेड पत्रकार वार्ता प्रस्तुत की वह भी कम चौंकाने वाली नहीं थी. इस कार्यक्रम में पत्रकारों को बोलने ही नहीं दिया गया. उनके बैठने की जगह पर मारवनलाल पत्रकारिता संस्थान के बच्चों को बिठा दिया गया. पत्रकारों को खदेड़ने के इस काम की जवाबदारी संस्थान के पीपी सिंह संभाल रहे थे.पत्रकारों के नाम पर जो सवाल पूछे गए वे सिंधिया को बोलने देने का मौका प्रदान कर रहे थे.इसके बावजूद सिंधिया अपनी ही पारी ठीक ढंग से नहीं खेल पाए क्योंकि सारा माजरा ऐसा बनावटी था कि सामने खड़े पत्रकार भी बैचेन हो गए. पत्रकारों का कहना था कि वे इस कार्यक्रम में सिर्फ खबर के कारण आए थे. संगठन से उनका कोई वास्ता नहीं.जिन पत्रकारों को इस संगठन के माध्यम से सरकार ने प्लॉट देने की योजना बनाई थी उन पत्रकारों के सामने तो मजबूरी थी कि जमीन मिलने तक हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं.इसके अलावा शावक पत्रकारों की भीड़ जुटाकर सिंधिया पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की गई कि मानों राजधानी के पत्रकारों का सैलाब इस संगठन की भू माफियाई गतिविधियों को भी समर्थन देता है.

यूनाईटेड न्यूज आफ इंडिया के मुखिया ए.के.भंडारी के प्रतिनिधि के रूप में लावण्य गुरुकुल की जमीन पर 115 प्लॉटों की एक ही दिन में रजिस्ट्री करवाने वाले शरद दिवेदी पत्रकारों को नेकनीयती की सलाह देते नजर आए. जबकि जमीन घोटाले की तलवार उनकी गर्दन पर लटकती नजर आ रही है और वे उस घोटाले में पत्रकार नहीं बल्कि चुरकट भू माफियाा नजर आ रहे हैं. जिस व्यक्ति को भंडारी जैसे व्यक्ति की चालबाजी ने जमीन घोटाले का अभियुक्त बना दिया हो वह इस कार्यक्रम में पत्रकारों का मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा था.

कहा जाए कि इस आयोजन में सिंधिया के व्यक्तित्व को काट छांट करके बोंसाई बनाने के प्रयास किए गए.उनकी तारीफ में जिस तरह कशीदे काढ़े गए उनसे लगता था कि मानों वे दूधपीते बच्चे के मुंह में बोतल की निपल पकड़ा रहे हों.

लोगों का कहना है कि यह सब हिंदुस्तान टाईम्स पत्र समूह में घुसपैठ के प्रयास थे. क्योंकि सिंधिया उस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं. जबकि वास्तव में यह सुनियोजित साजिश थी जिसके तहत सिंधिया के सूर्योदय को सांझ में बदलने का प्रयास किया जा रहा था.सिंधिया को कांग्रेस की राजनीति में हाशिए पर रखने के प्रयास क्यों हो रहे हैं.वे लोग कौन हैं जो गुलाम भारत की रियासतों में किए कए प्रशासनिक सुधारों के सफल प्रयोगों को आजाद हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देना चाहते. वे क्यों चाहते हैं कि हिंदुस्तान इसके पीछे किस प्रशासनिक अधिकारी का दिमाग काम कर रहा है और वह ऐसा क्यों कर रहा है.इसकी कहानी अगली किस्त में पढ़ें.

उपभोक्तावाद के दौर में पत्रकारों की नई आचार संहिता बने:अवधेश भार्गव

अवधेश भार्गव

हिंदुस्तान आज विकसित देशों की श्रंखला से बाहर निकलकर विकासशील देश बनने जा रहा है.इसके लिए पूरे देश के शासक और नागरिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं. गुजरात जैसे राज्य अपने सामाजिक संवाद के कारण आज पूरे देश में आदर्श राज्य बन गया है. यह सब इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुजरात की धरती पर सामाजिक परिवर्तन के प्रयोग सबसे ज्यादा किए. आज वहां के राजनेता भले ही गांधी की कार्यशैली से सौ फीसदी इत्तेफाक न रखते हों लेकिन वे थोड़ा न बहुत गांधी को अनुकरण करने का प्रयास जरूर करते हैं. यही कारण है कि आज गुजरात अपनी बुलंदियों को छूने के लिए बेताब है. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने इस राज्य की सोई प्रतिभा को नई अंगड़ाईयां लेने के लिए मजबूर कर दिया है. कहा जाता है कि ऐसी जागरूकता किसी साम्यवादी राज्य में ही आ सकती है. लेकिन संवाद की मोदी शैली ने उन सभी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया है. यह सब इसलिए हुआ क्योंकि गुजरात की धरती पर गौरव करने वाले गुजरातियों में विकास की ललक जगाने में मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी. आज वहां का मीडिया संवाद के नए सोपान पार कर रहा है. लोग कहते हैं कि मीडिया को आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए. उसे विकास के प्रति आशावान होना चाहिए. यह सब कहने वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था की परंपरा को चकनाचूर कर डाला है. मीडिया तो समाज का दर्पण होता है. समाज जैसा होगा वैसा ही अखबारों में झलकेगा. आज जब तकनीकी क्रांति का दौर है तब मीडिया में संवाद के नए रास्ते खुल गए हैं. अभी ज्यादा समय नहीं बीता जब किसी दूरदराज क्षेत्र से रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को अपनी खबर अखबार तक पहुंचाने में पसीना आ जाता था. कई बार तो उसकी खबर दूसरे दिन अखबार के दफ्तर पहुंच पाती थी. गांवों में संचार के साधन नहीं थे. फैक्स और फेसीमिल विधियां नब्बे के दशक में पहुंचीं. मोबाईल की तो शुरुआत बीसवी शताब्दी के पहले दशक में हो सकी. मोबाईल को लाने में भले ही देश के वैज्ञानिकों ने बड़ी लंबी यात्रा तय की हो लेकिन उसे जन जन तक पहुंचाने में पूर्ववर्ती एनडीए की सरकार के कार्यकाल में बड़े फैसले लिए गए. आज जब मोबाईल से संचार सरल हो गया है.मोबाईल टावरों का जाल बिछ गया है,तब अखबारों और चैनलों के पत्रकारों के सामने संवाद की एक नई दुनिया उजागर हो गई है. आज जरूरत है कि संवाद के सभी क्षेत्रों में पुरातन परंपरा से हटकर नई शैली विकसित की जाए. यह इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि देश ने पूंजीवाद को स्वीकार कर लिया है. आज समाजवाद और साम्यवाद या तमाम किस्म के वैचारिक आंदोलनों को जिंदा रहने के लिए पूंजीवाद का सहारा लेना पड़ रहा है. यही कारण है कि श्रमिक आंदोलनों की शैली भी बदल गई है. आज मुर्दाबाद और जिंदाबाद जैसे नारों का कोई वजूद नहीं बचा है. यदि श्रमिकों को लगता है कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं शोषण हो रहा है तो उन्हें अपनी बात कहने के लिए मीडिया का सशक्त मंच उपलब्ध है. मीडिया यदि इन सब बातों को उजागर करता है तो शासक वर्ग को मजबूर होकर अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होता है. यही कारण है कि आज मीडिया तीनों स्तंभों के बीच सबसे मजबूत चौथा स्तंभ बनकर उभर रहा है. यदि मीडिया किसी विषय पर सामाजिक संवाद आहूत करता है तो सभी स्तंभों को उस पर गौर करना होता है और फिर उसी के मुताबिक अपनी रणनीति बनानी होती है. मीडिया का ऐसी मौजूदगी पहले कभी नहीं देखी गई. आाजादी के संग्राम में भी मीडिया ने समाज के सभी कार्यक्षेत्रों की बातों पर चर्चा नहीं की.तब केवल आजादी के दीवानों को बढ़ावा देने के प्रयास हुए और अंग्रेजों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास किए गए. आज वैसा नहीं है. आज विकासवाद की नई परंपरा का श्रीगणेश हो चुका है. इसलिए आज के दौर में संवाद के चितेरों को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. इस विषय पर विस्तृत विमर्श जरूरी हो गया है. आज के पत्रकारों को नए नजरिए से संस्कारित करना जरूरी हो गया है. इससे समाज को भी नई दिशा मिलेगी और पत्रकारिता को भी अधिक प्रासंगिक बनाया जा सकेगा. अभी पूंजीवादी दौर से प्रभावित अखबारों पर उपभोक्ता वाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं. कहा जा रहा है कि अखबार वाले तो पैसे के लिए कुछ भी छापने तैयार रहते हैं. ये चर्चाएं मीडिया के हित में नहीं हैं. कुछ लोग अखबारों पर होर्डिंग छाप पत्रकारिता करने के आरोप लगाते हैं. यह सब इसलिए हो रहा है कि आज के दौर में मीडिया की कोई आचार संहिता नहीं है. पुरानी संहिता बेकार हो गई है उसे नया चोला पहनाए जाने की जरूरत है. नए दौर की पत्रकारिता के नए सिद्धांत बनाने में प्रदेश के पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थान असफल साबित हुए हैं.वे ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि उनकी पत्रकारिता प्रशिक्षण की शैली किताबी है. उनमें प्रशिक्षण देने वाले पत्रकार या शिक्षक जीवंत पत्रकारिता से कोसों दूर हैं. इसलिए जरूरी है कि अखबारी दुनिया से जुड़े पत्रकार ही तय करें कि वे किस तरह के मीडिया को समाज में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं. आज मीडिया से डरकर उसे सम्मान देने की परंपरा सी बन गई है. कई बार तो मीडिया कर्मियों के जबरिया सम्मानित किया जाता है. वह भी इसलिए कि इससे मीडिया से उनके संबंध सुधर जाएंगे. अखबारों की सुविधाएं बनेंगी और कम से कम इसी बहाने समाज में नाम हो जाएगा. लेकिन यह सब पाखंडी तरीके मीडिया को वास्तविक सम्मान नहीं दिला सकते. उसे सिर्फ उसके कामकाज के तरीकों और उससे निकले नतीजों के आधार पर ही समाज में प्रतिष्ठित कराया जा सकता है.कुछ साथी चाहते हैं कि उनकी गुंडागर्दी स्थापित हो जाए तो समाज उन्हें सम्मान देगा. लेकिन ऐसा नहीं है. भीड़ के नाम पर की गई इस गुंडागर्दी ने पत्रकारिता को क्षति ही अधिक पहुंचाई है. इससे समाज ने भले ही पत्रकारिता के इस स्वरूप के सामने चुप्पी साध ली हो लेकिन उसने ऐसी पत्रकारिता को अपना प्रेम नहीं दिया है. बेशक किसी भी सत्ता को स्थापित होने के लिए शक्ति की आराधना करना जरूरी होता है. लेकिन उसकी वास्तविक सत्ता तो प्रेम और विश्वास पर ही खड़ी हो पाती है. पत्रकारिता को भी आज सत्ता संधान के उसी मार्ग की दरकार है. जहां से वह समाज में प्रेम और विश्वास का संबल पा सके. इसके लिए उसे अपनी नई आचार संहिता बनानी होगी. यह संहिता आज के दौर से कदमताल करती होगी और मीडिया की जरूरतों के मद्देनजर बनाई जाएगी. इसके लिए हमें किसी इंतजार की जरूरत नहीं है.हम अपने सुझाव दें और मिलजुलकर ऐसी संहिता बनाएं जो पूरे देश और समाज को स्वीकार्य हो.बेशक इस विचार मंथन की प्रक्रिया में कई स्थापित सिद्धांतों और मानदंडों को हमें अपने ही हाथों तोड़ना होगा. इस प्रक्रिया से निकलकर बनी यह संहिता मीडिया कर्मियों की समस्याओं का निदान भी करेगी और आधुनिक पत्रकारिता को नई ऊंचाईयां भी प्रदान करेगी. ध्यान रहे यह पहल पत्रकार साथियों को ही करनी है.

पत्रकारिता को पूंजीवाद की गहराईयां समझनी होंगी

आलोक सिंघई

आज का दौर मीडिया के प्रचलित मानदंडों में भारी बदलाव का काल है. सूचना क्रांति के विस्फोट ने जानकारियों को उजागर करने में बड़ी भूमिका निभाई है. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी ऐसा ही एक औजार है जिसने आम नागरिकों को पत्रकार जैसा असरकारी बना दिया है. पत्रकार इस अधिनियम के माध्यम से शक्तिशाली बन गए हैं. क्योंकि इस स्रोत से उजागर होने वाली जानकारी और उस पर बनी खबरों को महज अफवाह बताकर खारिज नहीं किया जा सकता है. सामंतवादी शोषण और साहूकारी जुल्मों से कराहते समाज में सूचनाएं राहत की परी बनकर उपस्थित होती हैं और पीड़ित मानवता को वैचारिक आजादी की नई बुलंदियों पर पहुंचा देती हैं. यही कारण है कि आज सूचना क्रांति को वैचारिक क्रांति में तब्दील करने की जरूरत महसूस की जा रही है. यदि सूचनाएं किसी वैचारिक ब्यूटी पार्लर में सजधज कर निकलेंगी तो समाज में उनके प्रति बढ़ने वाला आकर्षण कुप्रबंधन और कुशासन की बेड़ियां पल में चकनाचूर कर सकता है. आज लोग कहते हैं कि हम भले ही आजाद हो गए हों लेकिन हमें आजादी दिलाने वाला लोकतंत्र गुलाम हो गया है. उसे गिरवी रखने में वैसे ही चंद बदमाशों के षड़यंत्र कामयाब होते नजर आ रहे हैं जैसा कभी सामंतों के दौर में हुआ करता था. लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी में ऐसे शोषणवादी सोच वाले तत्वों की घुसपैठ हो गई है. इन तत्वों ने कार्यपालिका को पंगु बना दिया है और विधायिका पर कब्जा जमाकर न्यायपालिका को असरहीन बना दिया है. कई मायनों में उन्होंने न्यायपालिका को खरीद तक डाला है. ऐसे में किसी स्वस्थ समाज की रचना कैसे संभव हो सकती है.इस व्यवस्था को बदलने के लिए आज एक नई सामाजिक क्रांति की जरूरत महसूस की जा रही है. इसके लिए किसी मोहनदास करमचंद गांधी की जरूरत नहीं है. यह परिवर्तन केवल लोगों की जागरूकता और मीडिया के सदुपयोग से संभव हो सकता है. मीडिया का सदुपयोग कैसे हो. क्योंकि मीडिया भी तरह तरह के लांछनों से कलंकित किया जा रहा है. पहले भी नेतृत्व के सामने यही चुनौती हुआ करती थी. भारतीय समाज हमेशा से त्यागियों और तपस्वियों का मार्गदर्शन स्वीकार करता रहा है. भारतीय साधु परंपरा में ऐसे ही समर्पित मनस्वी समाज का विश्वास अर्जित करते रहे हैं . अखबारों ने भी समाज का विश्वास पाया है. लेकिन पूंजी की दौड़ ने अखबार मालिकों के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. वे अपने सामने तकनीक और चमक दमक के बल पर आगे बढ़ते मीडिया को देखते हैं और धीरे धीरे उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं. इसके लिए भले ही उन्हें पाप कर्म करना पड़ें. अनैतिक साधनों का सहारा लेना पड़े. अपनी सफाई में ऐसा मीडिया कहता है कि हम क्या करें समाज ही तो हमें मजबूर करता है. दरअसल में हमने मीडिया को एक अलग संस्था मान लिया है. इस संस्था को हमने अपने भाग्य भरोसे जिंदा रहने को छोड़ दिया है.अब ऐसे में उसके कायाकल्प की कल्पना भी कैसे की जा सकती है. दरअसल मीडिया समाज का ही अंग है. हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा. यह मीडिया केवल सरकार या कार्पोरेट सेक्टर की पूंजी से जुड़ा तंत्र नहीं है. हमने उसके वैचारिक पक्ष को तो स्वीकार किया है लेकिन उसके आर्थिक पक्ष को हमने लगातार नजरंदाज किया है. एक पत्रकार से समाज अपेक्षा करता है कि वह बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़े. यह लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी इस पर समाज में कोई चिंतन नहीं चल रहा है. आजादी के संग्राम में समाज के पूंजीपति वर्ग ने अपने संसाधनों पर से अंग्रेजों का बढ़ता वर्चस्व हटाने के लिए मीडिया को पोषित किया था. इसीलिए तबके मीडिया के सामने लांछनों के अवसर नहीं थे. आज मीडिया को पैकेज संस्कृति के नाम पर लांछित किया जा रहा है. इस बातों में काफी हद तक सच्चाई भी है. लेकिन इसके लिए जवाबदार कौन है. समाज ने ही तो कारगर मीडिया की कमर तोड़ने के लिए नकली मीडिया को खड़ा किया. मीडिया में दोयम दर्जे के पत्रकारों की घुसपैठ कराई. अखबारों के मालिकों को मजबूर किया कि वे खबर लिखने वाले पत्रकारों के बजाए दुम हिलाने वाले मैनेजरों को बढ़ावा दें. आज जब यह विषबीज कांटेदार झाड़ियां बनकर सामने आ रहे हैं तो शिकायत की जा रही है कि मीडिया अपनी छवि सुधारे.अपना दायित्व ठीक तरह से निभाए. यह समाज जानता है कि बबूल का पेड़ बोकर आम नहीं पाया जा सकता लेकिन इसके बावजूद वह मीडिया में सुधार के उपाय करने तैयार नहीं है. आज शहरों में लाखों की तादाद में अखबार बंट रहे हैं. लेकिन उन अखबारों पर से जनता का भरोसा उसी प्रकार टूट गया है जिस प्रकार शासन व्यवस्था पर से जनता का भरोसा नहीं बचा है. यही कारण है कि लोग पैसा कमाते हैं पर टैक्स नहीं देना चाहते. शासन विकास की योजनाएं बनाता है पर लोग नक्सलवादियों को अपना समर्थन देते हैं. समाज को यदि इन समस्याओं से निजात पानी है तो उसे पाखंड आधारित जीवन शैली से बाहर निकलना होगा. उसे सही फैसले लेने वाले लोगों को आगे बढ़ाना होगा.उन्हें संरक्षण देना होगा और उन्हें अपना खुला समर्थन देना होगा. इतना ही नहीं उसे सामाजिक अपराध करने वालों को दंडित करने की प्रक्रिया भी सरल बनानी होगी. क्योंकि यदि वैचारिक गंदगी बढ़ाने वाली यह दौड़ जारी रही तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को असरकारी नहीं बनाया जा सकता. मीडिया इस जवाबदारी को अच्छी तरह संभाल सकता है.जरूरत है कि वह वैचारिक आधार पर अपना कोई एजेंडा तय करे और उसे लागू करने में पूरे समाज का सहयोग हासिल करे. ऐसा करने में मीडिया भी प्रतिष्ठित हो सकता है और पत्रकारों की कई समस्याओं का निदान भी चुटकियों में किया जा सकता है. यह सब संभव करने के लिए पत्रकारों और उनके संस्थानों को नए वैचारिक आंदोलन का श्रीगणेश करना होगा. यह वैचारिक क्रांति की अग्निशिखा समाज को नया मार्गदर्शन प्रदान करेगी. पूंजीवाद ने जब पत्रकारिता को बाजार में खड़ा कर ही दिया है तो उसे शोरूम बनाईए.

सत्ता के दलालों ने राजधानी में फैलाया जिस्म फरोशी का मायाजाल

इस लड़की को देह के बाजार में चालीस हजार रुपयों में नीलाम किया गया,

सुंदरता पर टिका कारोबार

क्या गालों पर चिकोटी लेकर दिलाई जाती है नौकरी

बाबा पुष्करानंद: धर्म की आड़ में दलाली का खेल

लोकतंत्र पर कलंक लगाने का प्रयास - संतो महंतो को गुमराह करके सरकार को ब्लैकमेल करने का षड़यंत्र

भोपाल(पीआईसीएमपीडॉटकॉम). काजू भुने प्लेट में व्हिस्की भरी गिलास में ,रामराज्य उतरा है विधायक निवास में । यह तीखी व्यंग्योक्ति कभी अखबारी दुनिया की चटखारे दार खबर हुआ करती थी. वक्त के साथ इन बातों का कोई असर नहीं बचा क्योंकि शराब खोरी अब आम हो चुकी है. लेकिन शराब के साथ शबाब का खेल आज भी चौंकाने वाला है. आम तौर पर अच्छे राजनेता इन बुराईयों से बचते रहते हैं. इतना होने के बावजूद अय्याशी और जिस्म फरोशी आज भी जारी है. वह तब और असहनीय होती है जब उसे बड़े सत्ताधीशों की उनींदी आंखें नजरंदाज करती हैं. पिछले दिनों ऐसी ही एक बाला को पुलिस ने सूचना मिलने के बाद अपनी हिरासत में ले लिया लेकिन जब कुछ ही देर में पुलिस के आला अफसरों के पास फोन पहुंचे तो खुद की नौकरी बचाने की जद्दोजहद शुरु हो गई और पुलिस ने उस बाला को आनन फानन छोड़ देने में ही अपनी भलाई समझी.

गुरेज तो इस बात का है कि यह देह का यह गंदा खेल एक धर्म के ठेकेदार के सहयोग से चलाया जा रहा है. मामला विधायक विश्रामगृह के सामने स्थापित कात्यायिनी शक्तिपीठ का है. यहां के महंत स्वामी पुष्करानंद को सत्ता के गलियारों में खासा सम्मान मिलता रहा है. चूंकि यह क्षेत्र विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिए आम तौर पर सरकार यहां के मामलों में दखल भी नहीं देती है. विधानसभा की एक अधिकारी तो इस शक्तिपीठ से ही शक्तियां लेती रहीं हैं और सत्ता के गलियारों में धमाचौकड़ी मचाती रहती हैं. ऐसे ही कई मंत्री,विधायक और अधिकारी भी धार्मिक कारणों से शक्तिपीठ के कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे हैं. स्त्री शक्ति का केन्द्र होने के कारण कई दिग्गजों का भी वरद हस्त इस मंदिर को मिलता रहा है.यही कारण है कि सुरक्षा के मसले पर तमाम मशक्कत के बावजूद शक्तिपीठ के मंदिर को प्रशासन ने यहां से नहीं हटाया. लेकिन विधानसभा के विशेषाधिकार में सेंध लगाता यह धर्म स्थल लड़की बरामद होने की घटना से एक बार फिर विवादों में आ गया.

पुलिस को सूचना मिली कि कात्यायिनी शक्तिपीठ में एक लड़की उमरिया से लाई गई है और उसे चालीस हजार रुपए की पेशगी पर जिस्मफरोशी के लिए भेजा जा रहा है. सहसा पुलिस को भी भरोसा नहीं हुआ और उसने कोई कार्रवाई करने से इंकार कर दिया. लेकिन जब पुलिस के कई अफसरों तक यह बात पहुंची तो जिला पुलिस ने डरते सहमते मंदिर परिसर में अपने सिपाही भेजे. उन्हें बताया गया कि यहां तो साहू समाज की किसी नवब्याहता की गोद भराई चल रही है. लेकिन जब सूत्रों ने बार बार पुलिस पर दबाब बनाया कि मंदिर के तलघर की छानबीन करें वहां उस लड़की को छुपाकर रखा गया है .उस लड़की के फोटो और वीडियो फिल्म भी मौजूद है तो पुलिस ने तलघर में जाकर लड़की को बरामद किया. उसे लाने वालों के फोन नंबर भी पुलिस को प्राप्त हो गए और अधिकारी तो तब चौंके जब बाबा के मोबाईल में कई दिग्गज राजनेताओं और उनके रिश्तेदारों के फोन नंबर भी प्राप्त हुए. बाबा पुष्कारानंद से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि इस लड़की ने जन अभियान परिषद में नौकरी लगवाने के लिए एक बड़े राजनेता के पिता को बीस हजार रुपए दिए हैं. जबकि हकीकत में यह बीस हजार रुपए लड़की को जिस्म फरोशी के एवज में दिलाए जाने थे. शेष बीस हजार रुपए सभी दलालों में बंटने थे. पुलिस इस मामले की तहकीकात करती लेकिन तभी जहांगीराबाद पुलिस अफसरों के पास फोन पहुंचने लगे और उन्होंने मामला बिगड़ने से पहले लड़की को महिला पुलिस थाने पहुंचाने में ही अपनी भलाई समझी.

पुलिस अभिरक्षा में लड़की कहती रही कि वह अपनी नौकरी लगवाने के लिए राजधानी पहुंची थी. उसे उमरिया के सैयद बाबा मंदिर लाए थे. अब कई सवाल खड़े होते हैं कि किसी मुस्लिम व्यक्ति को माता के मंदिर में जाने की जरूरत क्यों पड़ी. पुलिस ने दलालों के मोबाईल से किए गए काल रिकार्ड भी प्राप्त किए और तब जाकर हकीकत से परदा उठा. हकीकत तो यह थी कि यह लड़की इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि उसे चपरासन की नौकरी भी दिलाई जा सके. इसके बावजूद पुलिस ने उसे बीस हजार रुपए दिलाए और उसके घर भिजवाने का प्रबंध किया.

बाबा पुष्करानंद ने पुलिस को बताया कि उसने तो सबसे बड़े नेता के पिता को बीस हजार रुपए दिए हैं इसलिए लड़की की नौकरी जरूर लग जाएगी. यदि इस बात में थोड़ी भी हकीकत है तो यह शर्मनाक बात है.लेकिन यदि बाबा ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए यह तोहमत लगाई है तो यह बहुत बड़ा अपराध है और इसके लिए सरकार को बाबा का डेरा उखाड़ फेंकना चाहिए. सरकार में बैठे नेताओं को यह भी मालूम करना चाहिए कि बाबा का जिस्मफरोशी का यह जाल कितना बड़ा है. उसे किस किस नेताओं और अफसरों का संरक्षण प्राप्त है. वह नौकरी लगवाने के बहाने से क्या मंदिर आने वाली सभी कुंवारी कन्याओं पर भी बुरी निगाह रखता है.

भाजपा सरकार सहजता से मठ मंदिरों पर अपना स्नेह रखती है. इसलिए वह आमतौर पर मंदिरों के कामकाज में हस्तक्षेप भी नहीं करती. लेकिन कुछ महीनों पहले जब सुरक्षा के नाम पर विधायक विश्रामगृह से लगी झुग्गियां हटाने की मुहिम चलाई गई तो कात्यायिनी शक्तिपीठ से लगी गौशाला को भी विस्थापित करने की बात कही गई. तब स्वामी पुष्करानंद ने काफी हो हल्ला मचाया और कहा कि धर्म विरोधी लोग मंदिर तोड़ने का षड़यंत्र कर रहे हैं. उन्होंने राजधानी से लगे मंदिरों के मठाधीशों को भी बुलावा भेजा और मंदिर बचाने का अनुरोध किया. बाबा के बुलावे पर राजधानी के मठों के प्रभारी कात्यायिनी शक्तिपीठ पहुंचे. उनमें गुफा मंदिर के महंत चंद्रमादास, मोहनानंद ,मरयटिया हनुमान मंदिर के महंत शंकरदास, रविंद्र दास, स्वामी नवीन आनंद, संत दुर्गादास जैसे प्रतिष्ठित संत महंतों ने प्रशासन से पूछा कि मंदिर क्यों हटाया जा रहा है. तब विधानसभा के अधिकारियों ने बताया कि मंदिर को अतिक्रमण विरोधी मुहिम से कोई क्षति नहीं हुई है. उनके संशोधित नव शे में पंद्रह फीट गुणा बीस फीट का मंदिर मौजूद है लेकिन गौशाला का कोई हवाला नहीं हैं. तब सभी के हस्तक्षेप से बाबा को गौशाला विस्थापित करने के लिए भदभदा के नजदीक दो एकड़ जमीन दी गई. इस जमीन पर उन्हें मंदिर के साथ साथ गौशाला बनाने की अनुमति भी दी गई थी. गौशाला के लिए आवश्यक टीन और बल्लियां भी बाबा को प्रशासन ने ही मुहैया कराई थी. बाबा ने इस मौके का उपयोग किया और नई जमीन स्वीकार करते हुए उस पर गौशाला भी बनवा दी. इसके बावजूद उसने मंदिर से अपना डेरा नहीं हटाया.

अब जबकि मंदिर परिसर से चल रहे देह व्यापार के कारोबार की असलियत पुलिस प्रशासन के सामने आ चुकी है तब शासन को हस्तक्षेप करके इस कुरीती को बदलना होगा. यदि इस कारोबार को कुछ बड़े सत्ताधीशों की भी कृपा प्राप्त है तो भी धर्म को बदनाम करने वाले इस अड्डे को उखाड़ फेंका जाना जरूरी है. बाबा ने अपने बचाव में कहा है कि लड़की को नौकरी के लिए लाया गया था तो भी यह बात गले नहीं उतरती क्योंकि बाबा का नौकरी धंधे से आखिर क्या वास्ता. भारतीय समाज में साधु मार्गदर्शक होते हैं दलाल नहीं. फिर महिलाओं और लड़कियों के भड़ुए तो कतई नहीं हो सकते.इसलिए ऐसी किसी भी हरकत का विरोध पूरे समाज को करना होगा और बाबा की करतूतों से परदा उठाना होगा. (बदनामी से बचाने के लिए लड़की का नाम नहीं दिया जा रहा है.)

सहकारिता की आड़ में जमीन घोटाले करने वालों पर करें प्रहार

भोपाल (पीआईसीएमपीडॉटकॉम).तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर इन दिनों राजधानी में सहकारिता के नाम पर घोटाले करने वालों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है. लेकिन इस अभियान का लाभ आम लोगों को बहुत कम मिल रहा है. असली मुनाफा जमीनों की हेराफेरी करने वाले बिल्डर और भू माफिया की कमा रहे हैं. सहकारी समितियों के जिन सदस्यों को कालोनी में प्लॉट नहीं मिल पाए थे उन्हें सहकारिता विभाग उनके जमा कराए पैसे वापस दिलवा रहा है. ऐसे सदस्यों को बाकायदा ढूंढ़कर उन्हें उनकी जमा की गई मूल रकम लौटाई जा रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि आज उन जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं. सहकारिता के नाम पर जमीनों की बंदरबांट करने वाले भूमाफिया ने सहकारिता विभाग के अफसरों से गलबहियां करके यही प्लॉट आज के ऊंचे भावों पर बेचना शुरु कर दिया है. ऐसे ही कई घोटालों की खबरें हम लगातार आपको देते रहेंगे.अगर आपको भी कोई भूमाफिया से धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा हो तो कृपया इसकी सूचना हमें दें, आपकी लड़ाई हम पूरे दम खम से लड़ेंगे.

स्वत्वाधिकारी ,मुद्रक,प्रकाशक आलोक सिंघई ने सम्यक प्रिंटर्स से छापा और ऊपरी भूतल-7 अलकनंदा काम्पलेक्स जोन-1,एमपी नगर भोपाल से प्रकाशित किया.

संपादक - आलोकसिंघई
फो.2555007,मोबा.-9425376322
विशेषांक संपादक-नितिन वर्मा
मोबा.-9826047085
विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल.इ-मेल
Jasoos1967@yahoo.com